THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, with your permission, I beg to move:

That the Bill further to amend the Advocates Act, 1961, as

passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सर, यह जो एडवोकेट (अमेंडमेंट) बिल है, मैं इसके बारे में पांच-दस मिनट में, इसकी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री बताना चाहता हूं ।

सर, यह आजादी से पहले इंडियन हाईकोर्ट एक्ट, 1861 था । ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको बनाया था । इसका परपज़ था कि जो लीगल फ्रैटर्निटी है या लीगल प्रोफेशन में जो लोग हैं, जो वकील लोग हैं, उनका कोई रेग्युलेशन हो, इसलिए, यह एक्ट बना । फिर 1879 में लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट आया, उसमें सेक्शन 36 है, जिसमें touts का जिक्र आता है । Touts का मतलब है ठगी करने वाला, कुछ गलत बात कहने वाला कि मैं वकील हूं, लेकिन वह वकील होता ही नहीं है । जो व्यक्ति इस तरह के सब काम करता है, उनके लिए touts शब्द यूज़ हुआ है । (व्यवधान) इसको आप दलाली भी कह सकते हैं । इसके बाद 1920 में बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट बना । सर, आप तो इतिहास के बड़े जानकार हैं । आप चेयर पर विराजमान हैं । 1936 में इंडियन बार काउंसिल एक्ट भी आया । जब देश आजाद हुआ, तो यह विचार आया कि देश की परिस्थिति के अनुसार इसमें संशोधन होना चाहिए और अंग्रेजों ने जो कानून बनाए हैं, उनके अनुसार हमें क्यों चलना? हमारा लीगल प्रोफेशन भी एक नोबल प्रोफेशन है । इसके लिए लॉ कमीशन को एक मेनडेट दिया गया कि हम नई परिस्थितियों के अनुसार ज्यूडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़े रिफॉर्म्स करें । फिर ऑल इंडिया बार कमेटी भी बनी । इसके लिए उन्होंने कहा कि एक कमेटी और बना दो, फिर 1953 में, जब यह कमेटी बनी और उसकी कुछ सिफारिशें आईं, उसके बाद एडवोकेट एक्ट, 1961 आया, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं । इसका मूल परपज़ लीगल एजुकेशन को रेग्युलेट करने का रहा । इसमें बहुत से सुझाव आए कि क्या इसको रखना जरूरी है? इसमें एक सेक्शन 45(ए) है । वर्तमान में मैं जो बिल लेकर आया हूं, वह इसमें इनसर्ट करता है । उस समय touts को लेकर जो सेक्शन 36 था, उसके बारे में यह कहता है कि इसकी जरूरत है।

15.00 hrs

एक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सैक्शन 36 है, जो टाउट्स का जिक्र करता है, उसकी जरूरत है, ऐसा विषय आया । लोगों ने कहा कि इसकी जरूरत इसलिए है कि न्यायालय परिसर में दलाली नहीं होनी चाहिए । महोदय, इसलिए हमारे डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में एक कमेटी बनी थी, जिसके लिए लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के कमेंट भी लिए गए थे । इसके साथ-साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी सुझाव लिए गए । सभी ने यह बात मानी कि एडवोकेट्स एक्ट में संशोधन तो हो, यह जरूरी है, लेकिन इसमें टाउट्स से संबंधित प्रावधान अवश्य रखे जाने चाहिए, क्योंकि न्यायालय परिसर में दलाली ठीक नहीं है । जो ठगी करते हैं या जो दलाल टाइप के लोग वहाँ आते हैं, यह ठीक नहीं है ।

माननीय सभापति : दलाली कहीं भी ठीक नहीं है ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : दलाली कहीं भी ठीक नहीं है और इस समय तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है नरेन्द्र मोदी जी के कालखण्ड में ।

माननीय सभापति : जी-जी ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन अभियान चल रहा है । जब हर जगह साफ-सफाई का काम होना चाहिए तो न्यायालय परिसर भी साफ-सुथरा होना चाहिए । इसलिए मैं आपके समक्ष यह बिल लेकर आया हूँ । लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879 रिपील कर दिया गया है, क्योंकि यह कोलोनियल एक्ट है। इसमें मैं यह संशोधन लेकर आया हूँ, क्योंकि टाउट्स के संबंध में इसकी जरूरत है । इसमें एक कमेटी है, उसमें हाई कोर्ट के जज हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, इवेन कलेक्टर भी उसमें हैं । वे यह देखेंगे कि यह आदमी बार-बार कोर्ट परिसर में घूम रहा है, यह ठगी का काम करता है, तो ऐसे लोगों की वे एक लिस्ट बना देंगे । बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इसमें मदद करेगा । उस लिस्ट को न्यायालय परिसर में चस्पा कर देंगे । लिस्ट में नाम चस्पा होने के बाद भी अगर वह न्यायालय परिसर में पाया जाता है तो उसे तीन माह की सजा या 500 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं । मैं इसमें एक यह छोटा सा अमेंडमेंट लेकर सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ । मुझे

लगता है कि सदन इस पर सार्थक चर्चा करके इसको सर्वसम्मति से पास करेगा । जो चर्चा होगी, उसके बाद जैसा आदेश आप मुझे करेंगे, मैं जवाब देने के लिए फिर आपके समक्ष हाजिर रहूँगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

That the Bill further to amend the Advocates Act, 1961, as

passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

Sir, intermediation is a part of our Indian culture. Sometimes, people want an intermediary between them and whoever they are dealing with. It is a normal part of our culture. We also have intermediation in marriage alliances. Sometimes, in rural areas and in other parts of the country, people need intermediation even to reach out to people in authority and power. There is intermediation even in political parties; we know that. By and large, we welcome this Bill. Let me be very clear about that.

Sir, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. This is what Martin Luther King said. The right to seek justice is a fundamental right to our existence as a civil society. But because of the asymmetry in our society, in terms of education, access to people in authority, wealth, etc., an average person sometimes does not know how to navigate through the legal system. This is what is being exploited, and some people step in as touts to tell them who to engage and also tell them that if you engage this lawyer, this will work. Because of this asymmetry and the complexity of dealing with our legal system, touts thrive. So, these intermediaries thrive. In fact, there is a funny joke which I would like to say, and I hope that the lawyers do not get offended. As I myself am a lawyer, my parents are lawyers, and I come from a family of lawyers, I say this with full responsibility. The joke is that good lawyers know the law but great lawyers know the Judge. So, when that is the system, when an uneducated person has to come to court, it is quite natural that somebody has to intercede to help them navigate and connect with a right lawyer. This is what is happening everywhere. Because of this, many people flourish. Sir, my only quibble with this Bill is that it is targeting the tout in the small courts, the real small tout. In fact, in Tamil Nadu, there is a person whose name I do not want to mention but anybody from the legal fraternity in Tamil Nadu will completely know who I am referring to. Let us call him Judicial X. His speciality is to take temple *prasad* to every single Judge and to be photographed.

People say he can get the matter listed before a particular judge. Now the grapevine is that he can even appoint judges to the court. In fact, I would urge the Government to focus on these big fish instead of the small touts who are all operating only in the smaller courts. I agree there is a nexus between the touts and the lawyers, which must be broken. There is a nexus among the touts, the lawyers and the court staff because that is how the matters will come. Otherwise, the matters would not get listed. The worst is the nexus among the tout, the lawyer, the court staff and the judge. This definitely must go. So, we welcome this Bill. This Bill must make all efforts to break this nexus, penalise and punish people who are interfering in the justice system.

But the only fear I have is that this might be misused also. I am not going to particularly blame this Government. This Government is very famous for weaponizing the law. We all know what they have done with the ED. We all know what they have done with the PMLA. There, the original purpose of the law is something different but they completely misused it, weaponised it, and targeted people. They should not use this law and debar somebody who is a public interest litigant or who is an anti-establishment figure in the lower courts by branding him as a tout and disenfranchise him because a lawyer can also be a tout.

So, by and large, we definitely welcome this Bill but they should not use this as a weapon to disenfranchise and to debar legitimate anti-establishment lawyers in the lower courts. They must really focus on these big fish like the Judicial X whom I have named. They must really target them and use this law to go after them, and not go after others.

So, by and large, we welcome the Bill. We welcome the amendments you have brought about. But I hope you apply it fairly, implement it without any kind of discrimination, and it is not used in a weaponised manner in which you normally use other things. Thank you very much, Sir.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने सरकार द्वारा लाए गए बिल पर चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर दिया । हमारे प्रतिपक्ष के साथी श्री चिदम्बरम जी ने इस बिल का स्वागत किया है, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूं । उन्होंने इस बिल का समर्थन करते हुए कहा है कि बड़े दलालों को पकड़ना चाहिए और छोटे दलालों को छोड़ देना चाहिए । मैं कहता हूं कि दलाल तो दलाल है, जो एक्सप्लॉयटेशन करता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो । हमारी सरकार सभी दलालों के लिए यह बिल लाई है और हमारी सरकार केवल सड़कों पर या समाज में ही सफाई नहीं करती है, बल्कि न्यायालय में भी सफाई और स्वच्छता आ जाए, इसके लिए भी काम करती है ताकि लोगों को न्याय मिल सके। आज वह जमाना नहीं रहा जब कोई किसी वकील के प्रोफाइल को न जानता हो । आज नेट के समय में चाहे वकील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, तहसील कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, सभी की प्रोफाइल को हर कोई जान सकता है । पहले आप लाइब्रेरी में जाते, लॉ केसेज के बारे में पढ़ते, बार काउंसिल में जाते या किसी कोर्ट में जाते, लेकिन आप आज घर बैठकर ही किसी भी वकील के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी केवल शहरों तक सीमित नहीं है, आज गांव-गांव की महिलाएं भी अपनी डीबीटी चला रही हैं और सभी को टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इस तरह का वातावरण देश में बना है ।

सभापति जी, यदि हम हिस्ट्री देखें, तो वर्ष 1861 से हमें देखनी चाहिए । जब देश आजाद नहीं था, तब किस तरह से लीगल प्रोफेशन को या लीगल पेटिशनर को रेग्यूलेट किया जाए, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी । पहला हाईकोर्ट एक्ट, 1861 लीगल प्रोफेशन या लीगल पेटिशनर के लिए बना । उसके बाद लीगल पेटिशनर एक्ट 1879 में आया । आज 1879 के एक्ट को अमेंड किया जा रहा है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि आज़ादी के बाद नरेन्द्र मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधान मंत्री हैं, जिन्होंने लाल किले से कहा कि देश आज़ाद हो गया है, लेकिन जो कोलोनियल लिगेसी है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने दिया था, उसे समाप्त करेंगे । आज जब अमित शाह जी सीआरपीसी और आईपीसी में अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, तो वे यह क्यों लेकर आ रहे हैं? इसे हमारे सभी विद्वान वकील जानते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी, जिसे ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उसे उन्होंने दंड देने के लिए बनाया था और अमित शाह जी जो अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे हैं, वे न्याय देने के लिए है । इसलिए विपक्ष के लोगों को कम से कम दंड और न्याय में फर्क को जानना चाहिए । अंग्रेज किस तरह से लोगों को दबाना चाहते थे, किस तरह से लोगों को पनिश करना चाहते थे ।(व्यवधान)

कल्याण जी, आप सुन लीजिए । आपकी बारी आएगी, आप चिंता न कीजिए। (व्यवधान) लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879 आया, जिसके सेक्शन-36 का माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि उस सेक्शन-36 को ठीक करना हमारा कमिटमेंट है । यह कमिटमेंट हमारी सरकार का है, देश के प्रधान मंत्री जी का है । वह कमिटमेंट है कि कोलोनियल लिगेसी के जितने कानून होंगे या जो चीजें होंगी, उसे समाप्त करेंगे । इसको माननीय प्रधान मंत्री ने पंच प्रण में शामिल किया था । उन्होंने लाल किले से पाँच प्रण लिए थे, उसमें यह भी कहा था कि हम ब्रिटिश की गुलामी या दासता की विरासत को न केवल समाप्त करेंगे, बल्कि उसे ऑब्सोलीट कर देंगे। (व्यवधान)

You must have patience to listen to me. I hope everything will be clear. ....*(Interruptions)* Please talk to the Chair.

मैं लीगल टर्मिनोलॉजी पर बात कर रहा हूं, मैंने व्यक्तिगत तो कोई आक्षेप नहीं किया, मैं तो केवल अपने इस अमेंडमेंट बिल पर बात कर रहा हूं । अगर माननीय प्रधान मंत्री जी का बस नाम लेने से उन्हें चिढ़ हो रही है तो देश की जनता ने प्रधान मंत्री जी को, उनकी गारंटी को मान लिया है । अब ये कितना भी चिढ़ते रहें, जिस तरीके से तीनों राज्यों में परिणाम आए हैं, अब इनको सोचना चाहिए । इनके नेता का क्या बयान है? नेता जी कहते हैं कि यह भाजपा की जीत नहीं है, यह मोदी जी की जीत है । मैं अधीर रंजन जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि यह भारतीय जनता पार्टी की, जो मोदी जी के नेतृत्व में है, उसकी जीत है । इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद दूंगा ।(व्यवधान)

अधीर रंजन जी, आपने इस बात को एक चैनल पर कहा है । मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं । जब आपकी बारी आएगी, तब आप अपनी बात कह दीजिएगा। (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर। (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, जब आपको बोलने का समय दिया जाएगा, तब आप अपनी बात कह दीजिएगा । इसका भी उल्लेख कर दीजिएगा । अभी बैठ जाइए । जिनके नाम लिए गए हैं, उन सबको मौका दिया जाएगा।

श्री जगदम्बिका पाल: अधिष्ठाता महोदय, मैं पंच प्रण की बात कह रहा हूं। (व्यवधान) पंच प्रण में उन्होंने कहा कि all these Acts are part of the colonial legacy. ....*(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: You should not intervene like this.

SHRI JAGDAMBIKA PAL: Modi ji, in his speech on Panch Pran from Red Fort talked about giving up the colonial legacy. इसको समाप्त करने का फैसला किया है । आज उसका अमेंडमेंट लेकर आए हैं । मैं अपने लॉ मिनिस्टर

को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कोलोनियल लिगेसी को खत्म करने का काम किया है । हम उसी को ऑब्सोलीट कर रहे हैं, जिन्हें आप वेलकम कर रहे हैं । हमारा जो लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879 है, इस एक्ट को एबॉलिश करने में अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपीनियन हो, तो उस पर भी सदन चर्चा करे । मैं धन्यवाद देता हूं कि सदन में सुचारू रूप से कार्यवाही चल रही है ।

अभी चिदम्बरम जी ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही हैं । He said that good lawyer knows the law, and great lawyer knows the judge. आप तो उस फैमिली के हैं तो आपको क्या कहूं? हम तो आपको ग्रेट लॉयर मानते हैं । क्या आप जज को जानते हैं या आप एक गुड लॉयर हैं? मुझे लगता है कि सभी लॉयर्स कानून को जानते हैं और इसमें डिफरेंशिएट करना और यह कहना कि हम केवल जज से न्याय लेते हैं, यह निश्चित तौर पर किसी वकील का अपमान होगा । This Act abolishes the Legal Practitioners Act of 1879, the Act that dates back to 144 years. उसके बाद बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट, 1920 आया । फिर उसके बाद इंडियन बार काउंसिल एक्ट, 1926 आया । मैं इसके इतिहास में नहीं जाना चाहता, नहीं तो मैं बता सकता हूं कि हाई कोर्ट एक्ट, 1861 में क्या-क्या प्रावधान थे, जो अगर आज लोगों के ऊपर लगेगा तो उन्हें एक तरह से यह लगेगा कि यह गुलामी या दासता का प्रतीक था ।

चाहे लीगल प्रेक्टीशनर्स एक्ट, 1879 रहा हो, या बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट, 1920 रहा हो या इंडियन बार काउंसिल एक्ट, 1926 रहा हो, तो आज आप यह बताइए कि जब देश आज़ाद हुआ था, तब क्या था? आज तो लोग जाति की राजनीति करते हैं, पार्टी की राजनीति में सांप्रदायिकता करते हैं । उस आधार पर प्रत्याशियों को खोज कर टिकट देते हैं । देश में पहले, इन सदनों में आने वाले लोग, प्राय: लॉ बैकग्राउण्ड से ही थे । चाहे डॉ. भीम राव अम्बेडकर जी को मान लीजिए, चाहे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी को मान लीजिए, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मान लीजिए । ये कितनी बड़ी-बड़ी पर्सनेलिटीज़ थीं । इस तरीके से जो लोग उस समय लीगल प्रेक्टिशनर्स थे, उनको यह महसूस हुआ कि हमें कोई न कोई एक एक्ट ऐसा बनाना चाहिए, जिससे ऐसा काम हो । उसी के नाते एक एडवोकेट्स एक्ट, 1961 देश में आज़ादी के बाद बना क्योंकि इस बात को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी एवं सरदार वल्लभ भाई पटले जी ने महसूस किया था । इस तरह से यह टाइम के साथ हुआ था । जब समय कालांतर में बीतता रहा और जो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस के हीरोज़ थे, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जुड़े हुए थे, उन तमाम लोगों की एक लंबी श्रृंखला है, मैं सभी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसके बाद उन लोगों ने एक कमिटी बनाई और उस कमिटी के बाद, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स को लॉ कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया आदि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन किया गया और उसके बाद एक कम्प्रिहेंसिव टाइप का एक्ट एडवोकेट्स एक्ट, 1961 बनाना तय हुआ । आज हम इस लीगल प्रेक्टिशनर्स एक्ट, 1879 को ऑबस्लीट कर रहे हैं । केवल इसका जो एक सैक्शन था, लिस्ट ऑफ टाउट्स, मैं समझता हूँ कि उसी को ऑबस्लीट नहीं किया कि हम अभी भी देश की आजादी के बाद लिस्ट ऑफ टाउट्स के लिए कोई एक्ट न बनाएं, कोई कानूनी प्रावधान न दें । अभी भी गांव का गरीब आदमी अगर अपने कानूनी अधिकार पाने के लिए आए और अगर वह बीच में, उन कचहरियों में, कोर्ट्स में उन टाउट्स या दलालों के चंगुल में फंस जाए, जिस तरीके से आज देखते हैं कि लोग रेलवे या बस स्टेशनों पर उतरते हैं या कहीं कोई मरीज़ आता है तो किस तरह से उस स्थिति में भी वे टाउट्स उनके पीछे लगे रहते हैं कि आप इस हॉस्पिटल में चलिए, आप इस डॉक्टर के पास चलिए । तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से न्याय, जो सबसे बड़ी न्यायिक प्रकिया है कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय केवल मिलना ही नहीं चाहिए, बल्कि यह प्रतीत भी होना चाहिए कि लोगों को न्याय मिल रहा है । जिस तरीके से प्रधान मंत्री जी ने देश में एक स्वच्छता अभियान शुरु किया, आज वही स्वच्छता अभियान अगर न्यायिक प्रक्रिया में शुरू हो रहा है, मैं तो पूरे सदन से अपील करूंगा कि सर्वसम्मति से इसका स्वागत करके इसे पास करना चाहिए । आप देखिए कि इसके पहले भी हमने रिमूव किया है । ब हम जनविश्वास बिल ले कर आए थे, तब उसमें भी 183 प्रावधान थे । In that Bill, there were 183 provisions covering 42 Acts of 19 Ministries. उस मामले में देश ने तो शायद इतिहास बनाने का काम किया है । आप सौभाग्यशाली एवं साक्षी बने थे । आप उस कॉलोनियल लिगेसी को समाप्त करने के साक्षी हैं कि 19 मंत्रालयों के 42 एक्ट्स ऐसे थे, जिनमें केवल ब्रिटिशर्स की दासता को परिलक्षित करना था और उन्होंने अपने इंट्रेस्ट में वे एक्ट्स बनाए थे । पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन 19 मंत्रालयों के 42 एक्ट्स के सारे 183 प्रावधानों को ऑबस्लीट कर के देश की न्यायिक व्यवस्था में एक स्वच्छता देने का काम किया है । मुझे लगता है कि यह बात तो उसी दिशा में और आगे की पहल करती है ।

आज जो बिल लाया गया है, उससे निश्चित तौर से एक फायदा तो ज़रूर होगा । This is not a single legislation; this is a part of comprehensive mission of the Government to remove all the obsolete laws in this country. मान्यवर, यह तो क्लैरिटी है कि हम इस देश में जो भी हमारे एक्ट्स में हैं, सरकार प्रतिबद्ध है कि जो भी ऑबस्लीट लॉज़ हैं, उनको हम रिमूव करेंगे ।

आज मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो अमेण्डमेंट बिल है, यह कोर्ट में, उस न्यायिक प्रक्रिया में सुचिता और पवित्रता का काम करेगा या जिस तरीके से, removal of touts from the court premises करेगा और इसका अधिकार किसको होगा? सरकार को इसका अधिकार नहीं होगा । उस प्रेमाइसेस में टाउट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उन टाउट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए जो मिशन है, जो पावर दिया गया है, वह सुप्रीम कोर्ट के जज को है, हाई कोर्ट के जज को है । यह साफ है कि की-फीचर्स ऑफ दी बिल इंक्लूड है । The Bill provides that every High Court, district judge, sessions judge, district magistrate, and revenue officer not below the rank of District Collector, यह नहीं है कि कोई ऐसे आईएएस जो जुनियर हों, वह आईएएस जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, who is responsible for looking after all the revenue cases and revenue affairs, he can exercise this power या तो हाई कोर्ट का जज या डिस्ट्रिक्ट जज होगा, यह

अधिकार न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए लोगों को दिया गया है । यह कोई एक्जिक्यूटिव पावर नहीं है । यह कोई सरकार या प्रशासन के अधिकार में नहीं आ रहा है कि हम किसी को टाउट बना देंगे या किसी के खिलाफ आइडेंटिफाई करके उसको पीनलाइज़ कर देंगे । यह अधिकार हमने सीधे-सीधे हाई कोर्ट के जजेज को दिया है, हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज को दिया है, सेशन जज को दिया है और रेवेन्यू में जो मुकदमें देखते हैं, उनको दिया है ।

मैं समझता हूं कि tout refers to a person who procures the employment of a legal practitioner in a legal business in return of any payment - यह तो साफ है - and frequents places such as the premises of civil or criminal courts, revenue offices or railway stations to procure such employment. इस तरीके से घूमकर जिन गरीब लोगों का शोषण किया जाता है, मुझे लगता है कि इसको रोकने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है । यह कानून केवल एक जगह लागू नहीं होगा, बल्कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लागू होगा । सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट और नीचे के कोर्ट में जिस तरह से न्यायिक प्रक्रिया और इस कानून में अमेंडमेंड होने के बाद न्यायिक प्रक्रिया की लिए जो स्वच्छता आएगा, वह देश के लिए ऐतिहासिक वरदान साबित होगा ।

इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि The Court or judge may exclude from the premises of the Court any person whose name is included in the list of touts. आप प्रिपरेशन ऑफ दी लिस्ट देखिए कि क्या है? The authorities empowered to frame and publish the list of touts may order subordinate courts to hold an inquiry into the conduct of persons. ऐसा नहीं है कि किसी इनोसेंट या साधारण आदमी को भी इस तरीके से कर दिया जाएगा । उसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी होगी । Courts to hold an inquiry into the conduct of a person alleged or suspected to be touts. जिसके बारे में ऐसा होगा कि वह कोर्ट में लगातार है और टाउट्स की भूमिका निभा रहा है, लोगों का शोषण कर रहा है, लोगों के लिए दलाली का काम कर रहा है, ऐसे लोगों को उनके कंडक्ट की इंक्वायरी होगी और तब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी । Once such a person is proven to be a tout, his name may be included by the authority in the list of touts. No person will be included in such lists without getting an opportunity of showing cause against his inclusion. ऐसा भी नहीं है कि किसी का नाम डाला जा सकता है । पेनाल्टी साफ है, Any person who acts as a tout while his name is included in the list of touts will be punished with imprisonment up to three months, a fine up to Rs. 500, or both.

मान्यवर, इस तरह से आज हम पहली बार उस एक्ट को आब्सलीट कर रहे हैं । उस एक्ट को आब्सलीट करने के बाद जिस तरीके काम हो रहा है, पहले के कैसे वकील थे, आपको याद होगा, मैं वेस्ट बंगाल की बात करता हूं । अभी कल्याण जी बात कर रहे थे । महर्षि अरविंद का केस हुआ था । उस समय खुद सी.आर. दास जी ने अपनी सर्विसेज उनको दिया था । यदि हमारे अधिवक्ताओं के इतिहास को देखा जाए तो शायद वह स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है । ऐसा नहीं है कि किसी को कहीं ले जाने की जरुरत है । महर्षि अरविंद के खिलाफ केस हुआ, उसमें वह नहीं थे । इसके बावजूद सी.आर. दास जैसे एडवोकेट्स ने उनको जिस तरीके से अपनी सेवाएं दी, उनके लिए काम किया । आज हमारे अधिवक्ताओं का इतिहास अपने-आप में बहुत बड़ा है । इससे एक कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनेगा, जिसमें एडवोकेट्स एक्ट 1961 है, जो इस एक्ट से रेगुलेट करेगा, इस देश में जो प्रैक्टिस ऑफ लॉ है, उसको करेगा । यह बिल जो पीनलाइजिंग है, वह प्रैक्टिस ऑफ टाउटिंग अण्डर दी एडवोकेट्स एक्ट है । एडवोकेट्स एक्ट के नाम के अंतर्गत अगर वे कोई टाउट करते हैं या इस तरीके का काम करते हैं तो यह केवल उन्हीं के लिए है । आप देखें कि इस बिल को कितनी चर्चा करके लाया गया है । This legislation was also recommended by the Law Commission of India.

लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 249वीं रिपोर्ट में देखा जाए, in its 249 th Report titled Obsolete Laws: Warranting Immediate Repeal. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 249वीं रिपोर्ट में भी एक तरह से सरकार को रिकमेंड किया है कि इसको आब्सलीट किया जाए और इसमें इमीडिएट रिपील करने की एक अपेक्षा की गई है । सरकार उसी के अनुरूप इस बिल को लेकर आ रही है । इस कानून को लाने के पहले इस सरकार ने इस बिल पर सभी जो वैरियस स्टेकहोल्डर्स हैं, जो लीगल प्रोफेशन में लगे हैं, उनसे बात की है । इंडिया का सबसे लीगल प्रोफेशन कौन है, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और बार काउंसिल उनकी सबसे बड़ी आर्गेनाइजेशन है । ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस अमेंडमेंट को अपने आप लाने का काम किया है । जो लोग या संस्थाएं सीधे तौर से देश की न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करने वाले अधिवक्ता हैं, जो न्याय की प्रक्रिया की व्याख्या करने वाले कोर्ट्स में वकील हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ भी हमारी सरकार ने एक कांप्रिहैंसिव बिल बनाने के लिए कंसल्ट किया । इस कंसल्टेशन के बाद इसे शामिल करने की बात आई कि touting in the legal profession is against the spirit of the profession. स्वयं अधिवक्ताओं ने माना है कि न्याय दिलाने की जो भावना है, जो हमारे प्रोफेशन की भावना है कि हम किसी पीड़ित को न्याय दिला सकें । अधिवक्ता का काम पीड़ित को न्याय दिलाने का है । माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि वर्ष 1961 का जो अमेंडमेंट है, उस एक्ट में हम केवल सैक्शन-36 को जोड़ने का काम कर रहे हैं । यह इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि सैक्शन-30 जो लिस्ट ऑफ दी टाउट्स है, उसको एनालाइज करने के लिए या न्यायिक प्रक्रिया की स्वच्छता के लिए इसमें जोड़ रहे हैं । यह बिल रिपील कर रहा है, कुछ certain Sections related to touts under the Legal Practitioners Act, 1879 है, जिसे हमारे मंत्री लेकर ऑब्सलीट करने के लिए लेकर आ रहे हैं और उसके एक सैक्शन 36 को इसमें जोड़ने के लिए इसे लाए हैं ।

Now, the 1961 Act consolidates the law related to legal practitioners and constitutes Bar Councils and the All-India Bar Council. मुझे लगता है कि आज सदन के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और पूरा देश इस बात का साक्षी बनेगा, गवाह बनेगा कि पूरे देश में छोटे कोर्ट से लेकर, तहसील, मुंसिफ, मजिस्ट्रेट के कोर्ट से लेकर, सैशन जज के कोर्ट

से लेकर, डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट से लेकर, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक न्यायिक प्रक्रिया को बिना किसी टाउट के, बिना किसी बिचौलिए के किया जाए । मैं अपील करूंगा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करें ।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, thank you very much for the opportunity that has been offered to me to speak on this small Amendment.

Sir, when this Parliament discussed the 42 nd Amendment -- the biggest controversial Amendment -- it was said that the legislative competence of the Parliament cannot be questioned in the court of law. This triggered the controversy. Ultimately, it was settled down later by virtue of the 44 th Amendment.

The legislative capacity of Parliament could not have been questioned in those days. Now, Parliaments capacity of legislation has become a mockery through this Bill. I do not know how this Bill was drafted without giving any due care for the legislative competency of this Parliament.

Ever since this BJP Government came into power, Parliament is being misused. Most of the State-subject laws were brought here for amendment encroaching the State power. Ultimately, the State autonomy and cooperative federalism became a laughing stock. It is a small Bill but I am not able to understand the way nationalism was put up everywhere even in the Advocates Act. The hon. Minister talks about colonial law. In 1879, the provision was there. You want to repeal it. But by way of repealing it, you are introducing the same section, importing the same section in the new law. What does it mean? Is it not the same colonial law? I am not able to understand the rationality of the Government behind this amendment.

Again, the simple reading of how a person can be listed as a tout, I quote: The passing of a resolution declaring any person to be or not to be a tout by majority of the members present at the meeting. Who are all the members of the Committee? Nothing is mentioned. Then, it says, by evidence of general repute. Evidence must be tendered by a person who is having reputation in the society. It is all right. The next sentence is very dangerous-or otherwise. What happened to Article 356? A State Government can be dismissed On the recommendation of the Governor or otherwise. The word otherwise was used by the President when the Tamil Nadu Government was dismissed without the Governors recommendation. It is such a dangerous provision for small Advocates Act. You are putting the same otherwise here. How is it going to be used or misused, nobody can say that.

Coming to the meaning of tout who procures, in consideration of any remuneration moving from any legal practitioner. What does it mean? Money will go from the pocket of the advocate to the tout. This House many times has discussed corruption at length. The Prevention of Corruption Act has been periodically amended which says that not only the receiver, but the giver of the money is also a culprit under the Act and he has to be convicted. The tout is going to be eliminated and given imprisonment or penalty. Does it not mean that the person who is giving money is also liable to punishment? What type of justice are you rendering to A and B between whom the money is exchanged? So, the very purpose of the Prevention of Corruption Act itself is defeated here the way in which the Bill is drafted.

For the first time I have come across a Bill which has been submitted to Parliament, I may be correct or not, in which the objects and reasons were not at all given. For what purpose are you going to introduce this Amendment? I want to know whether the Bar Council of India is going to be consulted when a person is going to be listed as tout. What will be the role of the Bar Council? Sir, former Chief Justice of India, Justice Bharucha, a decade ago said in the open meeting on the eve of his retirement that 20 per cent of the judiciary has become corrupt. He made an open statement. The only problem for the litigant is that if a man is having case in a particular court, the judge will come under 20 per cent or 80 per cent. How would we know it? So, you want to keep the entire judicial system clean, but for a small matter, you are not able to draft a clear law to serve the purpose. What type of purpose is it going to serve? Nothing. Ignorance of law is not an excuse. That is a legal maxim. A person cannot claim that he did not know the law. What about the society? Still, 30 per cent of people are illiterate so far as law is concerned; 70 per cent of people are unaware of the legal system.

If you want to regularize the system of touts, frame some reasonable guidelines by permitting or not permitting them. A healthy discussion must be there in all the forums including the Bar Council of India. After the examination done by the Bar Council of India or Supreme Court Judges, a man has been designated

as Advocate on Record (AoR). A senior advocate designated by the High Court and Supreme Court cannot be Advocate on Record. (*Interruptions*) AoR is afraid; senior advocate is afraid. Who is approaching the senior advocate? Is it the litigant? No. It is AoR. The role of the Advocate on Record becomes quite similar to that of a tout as far as the senior advocate is concerned. So, a judicial system needs some middlemen to bypass every loophole in the judicial system. It is a question whether that must be eliminated or that may be regularized with a rational application. That is a question before this House. I think that this Bill is having no meaning at all because you are just mechanically transporting a section which is available in 1879 Act to the new Act without application of mind. My only question is this. What type of exercise has been done by the Government? What inference has been drawn from this 100-year old law? Is this provision essential or the provision is workable or has the practicality of the provision been applied? Nothing has been done by this Government. But you want to remove the corruption in the name of Narendra Modi starting from small Bill up to a big Bill. So, my only submission is this. Do not make this Parliament a laughing stock. Do not do the meaningless exercise for which the competency of the Parliament is undermined. So, re-visit the law, take back this law, draft carefully, try to re-visit, try to regularize, or try to make a system which is workable in the judicial system.

With these words, I conclude my speech.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I want to draw the attention of hon. Law Minister, through you. The first question is, whether every category of touts in the field of law has been brought within the ambit of this Bill? Is it correct? Touts are everywhere, from the lower judiciary up to the Supreme Court. But through these types of Bills, practically you are identifying few persons who are in the subordinate courts or the district courts. Where is the real intention to identify the touts? I understand, and what Mr. Raja has just said, that this Bill is a replacement of the old provision of the Legal Practitioners Act. Nothing more than that. You are taking provisions from that colonial Bill. I have no difficulties, but when you are making an attempt to bring this Bill, what do you think? There are a number of touts. Sir, I will tell you one thing. It is very easy to identify touts among the poor. How many touts are there in the judiciary who are extremely sophisticated? Can you identify them? I understand the process you have started and I appreciate it, but the reality is that touts are everywhere. Sophisticated tout is there. Tout is there going to five star hotels, tout is there going to seven star hotels, tout is taking you to different places of the country.

They are coming from very big universities. They are having Mercedes. You cannot identify those touts. That is exactly what I am telling. You are not bringing all types of touts. Today when the discussion is there, let the discussion go on; I know it will not be done now. Think in future about this.

Let me explain myself. What we know about this? We have laws. What are the laws? There is a statute law. There is a case law. These laws, statute law and case law, are known to everyone which are applicable in a court. All we proceed. There is another law which is called face law. Face law is important for having an order from the higher judiciary, highest judiciary. That is the practical thing. For the face law, litigants have to spend lakhs and lakhs of rupees. You have to invest Rs.20 lakh. You have to engage a lawyer for Rs.20 lakh; you will get the order. Touts are everywhere. Who are the touts? That is the whole difficulty. Identification of a tout is necessary. It is very easy to identify a poor man. A lawyer is a tout. Bring a system, introduce a system to identify a real tout in the Judiciary, in the judicial system itself. What has been said is correct. It is every day experience. Today, our Judiciary has become too much expensive. Unless you engage a very big face in the Supreme Court, you cannot have an order. Good money, good law, good justice: this is the practical thing in the country. That is going on. You identify them. I would request you to think where the real tout is. There is one grade of lawyers amongst whom some pose themselves that they can bring the judgement, they can bring the order from the highest court, they can bring the order from that Judge. Sitting in a five-star hotel, everything is settled. He is the main tout. Where is the procedure? How you are identifying him?

Since you have brought the Bill, I have got the chance to speak. I was thinking for decades together what is going on. I am a man of practical field. I am looking into these things. Regarding these types of touts, I will not say about all the Judges, but of course, very few Judges are there in our country having a very good relationship with them. In this dinner party, they will go. In their lunch party, they will go. In their marriage anniversary, they will go. We know everything. Everything is known. Someone speaks for two minutes and gets five-minutes face. Face law is very important in our country today to have an order, to get the justice. Who is getting that? Rich people are getting it, not the poor people. Can you think about this countrys

Judiciary today? Lakhs and lakhs of poor people are not getting justice. Their cases are pending before the Supreme Court decades after decades. But the Supreme Court is very much concerned whether there would be marriage of the same sex or not. Therefore, a Constitution Bench will see and they will go on hearing day in, day out. It is a peculiar thing. Problems of the sophisticated people, rich people would be entertained by the Supreme Court. I will tell you, whether the same sex marriage is to be done or not, regarding that, within three days a Bench has been constituted, matter has been heard, and everything has been done. Do you know that for long 27 years, a Seven-Judge Bench of the Supreme Court is not hearing one matter which really pertains to the poor agricultural worker of West Bengal?

Can you imagine that? For whom does the Judiciary exist? Does the Judiciary exist for the purpose of resolving the problems of only the most sophisticated and rich people?

I will tell you about one incident. I am sorry for taking much of your time. This incident happened in the court of Justice Dattu, the former Chief Justice of India. I was present there at that time. I will not take the name of a very senior and famous lawyer. He wanted to mention a matter with regard to one industrialist before the court. I must say that the former Chief Justice of India, Justice H.L. Dattu said to the lawyer, Mr. so and so, I have a number of matters of poor workers and poor people of this country. I do not have time. Simply because you are appearing for the top industrialist, leaving aside everything, I have to take up your matter. I have had it. But todays approach is different and peculiar. I am not taking any name. There are big corporates. There are big lawyers. Give it to big lawyers. Go and mention about it, and his matter will be taken up. What is happening in our country? Poor people are being ignored.

Hon. Chairperson, Sir, this phenomenon has been going on. The point is about identified touts and non-identified touts. You are trying to identify touts. But there are big arenas, places, fields, etc. where non-identified touts are there. Nobody will tell you. They are not taking tea in the street shops. They are taking tea in five-star hotels, and they are not identified there. How can you identify and remove a highly-paid lawyer-cum-tout? They accept it. Do not worry. Do not worry about Rs. 50 lakh. Get the order. The order is coming. If he is not there, engage someone else. That is because of face law. This is happening. Touts are there.

Now, I am coming to a very relevant question. Tout is there when a relative of any judge is in the field of a legal practice. Tout is there. Taking the name of the Judge, his relative is also holding out threats. It is appearing in the newspapers. I do not want to take the names. It is appearing in the newspapers. It is under investigation. Let it be investigated. Since I have got the chance, I just want to tell you one thing. Hon. Law Minister, I do not have any difficulty with regard to transfer. I want it. I wish for it. But what I really want is that there should be a policy. Unless a policy is there, transparency would not be there. You transfer anybody. I am not concerned with it. Give a policy. At least, 140 crore people of this country will understand that this is a policy and, on that basis, transfers would be made. But what is happening today? You are picking up and transferring. Transfer all the judges whose relatives are practising in any High Court. Why are you transferring a Judge from the High Court to Supreme Court knowing very well that his relatives are practising in the Supreme Court itself?

Why are they picking up the names? If I am unfit, if I am dishonest, if I am not fit for a court, then I am not fit for any other High Courts also. The point is very simple.

Then, comes the issue of tout. They say that tout will save. This is the problem that has to be addressed. Of course, I support this Bill but I am on a very larger issue to save the Indian Judiciary for future generations. I am almost at the fag end of my legal service, maybe for eight or ten years, I will be in this profession. But generations after me should not face the pain which I had faced and the things which I have seen. You know about the problem. I have told about it somewhere also.

You know why judges are saved. The Supreme Court and the High Court Judges can be criticized only when I am here. It is because of the privilege given by the Constitution. It is because of the existence of the contempt of court. No one can criticize about the judges activities. Otherwise, they will be held up for contempt of court. The judges of our country are saved only because of the contempt of court. Do not think everyone is perfect and everyone is correct. There are so many persons. Earlier, I used to take it that it may be an abberation. Sorry, today, I do not take it. It has become a great disease of the Indian Judiciary and that disease has to be resolved.

I know you are having a limited power. I know that but this is the field and this is the place where I can tell my words, Let the highest court of this country take note of the contents which I have said.

Thank you, Sir.

SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): Thank you Chairman Sir for giving me an opportunity to participate in this discussion of the Advocates (Amendment) Bill, 2023. There is nothing to oppose in this Bill. I fully support it. This is a welcome step.

Advocates are an important part of Judicial system. They are not only the officers of the Court but they also act as an important bridge between those who seek justice and those who are empowered under the law to give justice.

The amendments to the Advocates Act were long pending and bring about a critical reform in the justice delivery system of our country.

The importance of these amendments cannot be understated. While these amendments are important, questions can only be raised when the State agencies act against lawyers.

Secondly, the enforcement mechanisms will be required to implement this law. This is because while we want that so called Munna-Bhai lawyers are punished, procedures also need to be brought about to ensure that there is no unnecessary persecution of any genuine lawyer and through these amendments, the independence of Judiciary is not hindered.

One of the most crucial components of the justice delivery system in India is its human resource element which is the Advocate. Their role cannot be understated in the whole process. They act as a bridge between the aggrieved and the adjudication institution. They also play an important role in shaping our society and not to forget their role in assisting courts to arrive at several judgements protecting the environment.

In 2017, a two-year long verification drive by the Bar Council of India found that only 50 to 60 per cent of practising lawyers in India were genuine. This number was heavily reported in the Media.
There needs to be a single public register for all the advocates across the country, which can be accessed by the public to cross verify the claims of educational qualifications of the advocates.

Advocacy may look like a very glamours profession, but for those who are in the practice of law, it is far from the truth. The Advocates Act needs to be further amended to ensure that certain benefits of social security are also extended to the junior advocates and to ensure that advocacy as a profession can retain the best talent. In this regard, there is no provision.

I would like to suggest to the hon. Law Minister to take steps to ensure that first generation advocates are also benefited from the targeted Government schemes for health, housing and other schemes so that they may be able to earn a respectful livelihood. Despite the importance attached to this profession, there are no concrete measures in place to ensure the social security of the advocates. Even a new lawyer in Delhi has to pay around Rs.15,000 as enrolment fee in Delhi Bar Council. Charging fees beyond what is prescribed under Section 24(1) (f) of the Advocates Act, 1961 violates the Right to Equality under Article 14 and denies opportunities to aspiring advocates. I may inform the hon. Law Minister that the poor advocates are not in a position to pay the enrolment fees. In this regard, the Central Government has to take some steps to provide minimum financial assistance to the rural advocates, particularly for constructing their houses, paying the enrolment fees etc. Our hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y. S. Jagan Mohan Reddy is giving Rs. 5000 per month to all the junior lawyers. For that, we should appreciate the Andhra Pradesh Government.

To strengthen this Amendment Act and also to implement the ideas of Dr. B.R. Ambedkar, the Union Government has to take steps to introduce All India Judicial Service, particularly for the appointment of judges in all the courts including Supreme Court. It will be impartial like IAS and IPS. It will render some service for the rural people. Otherwise, people will not be able to get justice from the courts. Therefore, I am requesting the hon. Minister to introduce All India Judicial Service in the country.

Regarding touts, in all the departments touts are there. It is not possible to eliminate them fully. The Union Government has to take steps to curb the tout system. Thank you, Sir, for giving me the opportunity.

16.00 hrs

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Chairman, Sir. At the outset, I should make it very clear that the Bill is relating to advocates and it is not relating to functioning of courts or the High Courts or the Supreme Court. Our attempt while deliberating on this amendment Bill is to strengthen the advocates of our country and the system of jurisprudence in our country.

This Advocates (Amendment) Bill clearly mentions two things. One is to repeal all obsolete laws of Pre-Independence Act, not totally but which have lost their utility. This should be borne in mind. All the laws are not being abolished. Those laws which have lost their utility are being removed and the Government of India is doing this in consultation with the Bar Council of India. So, these two things have to be borne in mind when we are deliberating on this subject. We know the history of Indian High Courts, how they were formed by an enactment of British Parliament in 1861, and subsequently what development has taken place in between.

While going through the Bill, Sir, the definition of tout is also given: A tout means a person who procures in consideration of any remuneration moving from any legal practitioner, the employment of the legal practitioner in any legal business. This is the first part of the definition. But subsequently, in the second sub-para, it is mentioned: The purpose of such procurement frequents the precincts of Civil or Criminal Courts or of revenue offices or railway stations, landing stages, lodging places, or other places of pubic resort. So, in that respect, it has been very clearly mentioned in the Bill that those touts who operate for lower courts need to be apprehended and named. Their names should be published so that they can be prosecuted. The impression of the Government or the earlier law was that touts do not exist in High Courts or in the Supreme Court. We should not presume that touts do exist. But my only humble suggestion is that a beginning is being made. It was there in the earlier enactment which is now getting incorporated in this amendment, the Advocates (Amendment) Act, through this Bill and the best part is that the previous law which was there, now one cohesive law is coming into existence. This was introduced and passed in Rajya Sabha last August. It amends the Advocates Act 1961. This Bill repeals certain Sections related to touts under the Legat Practitioners Act 1879. The Bill provides that every High Court, District Court, Sessions Judge, District Magistrate, and Revenue Officer not below the rank of District Collector can frame and publish a list of touts. This Bill makes the act of tout punishable. Hence, cases can be filed against them and they can be apprehended.

There are two aspects on which I would like to deliberate. One is about the legal practitioners, the advocates. What needs to be done for them? The second is about Rule 45. That is relating to regulating legal education. That also needs to be looked into. That has not been addressed in this Bill. There is Rule 36 which imposes three primary restrictions on lawyers. Firstly, lawyers are not allowed to promote themselves directly or indirectly. Secondly, if the lawyers are involved in a case, they cannot advertise themselves in the Media, newspapers, and display their photo or make inspirational comments.

The question is this. Who is going to question the lawyers? Who is going to lodge a complaint of this type of dereliction of duty? Our expectation is that the Bar Council of India will take cognizance of it, deliberate on it, and take action on it. But are they doing that? During the last 20-30 years, since the inception of Bar Council of India, how many such cases have been deliberated by the Bar Council? Not a single complaint has been lodged. Or, has it been lodged and it has been lost over? In consultation with the Bar Council of India, the Government is repealing the Legal Practitioners Act, 1879. Now, the legal profession will be regulated by a single Act. It is their responsibility to have quality lawyers. Section 36 of the 1879 Act is incorporated in the Advocates Act 1961.

Here, I have to make some suggestions for the consideration of the Government. Reform is a continuous process, and it has to be done with the tune of time. There should be provisions for professional development of lawyers in the Advocates Act 1961. There is no such provision even today. How can an advocate enrich himself professionally? Technology has become pervasive now. There are many emerging frontiers of law. Law to regulate telecom sector, law on intellectual property rights, and Arbitration Act are

some of them. Now, online dispute resolution has become a practice. Lawyers need to update with the latest development in the field of technology. Should we not bring in these aspects in our amendment? The aspect of how to make them more professional is missing. I would suggest and the Government may consider that there should be a national electronic register for advocates. Anyone sitting anywhere in the country can find out who are the advocates. Why should they take the help of touts? Or, why should we presume that without a middleman, we cannot approach a lawyer? We do not have any such register.

The Law Commission, in its 184th Report had suggested that there should be a single database. This would be good to bring social welfare schemes for the lawyers also as there would be a single database of the whole country. There should be a digital interface between the advocates and the clients. This will eliminate the need for Section 45A in itself. Why do we need middlemen when we can have an electronic platform that can connect advocates and clients? I have a query also. Do we need intermediary that is being incorporated as Section 55 in the Advocates Act, after repealing Section 36? When we have digital interface, is this provision necessary?

Finally, I would come to the Advocates Protection Act. The States have enacted such law. The Minister of Environment, Forest and Climate Change is also present here in this House. Rajasthan has enacted that law. The present Law Minister is also from Rajasthan. Rajasthan has enacted a State law. I am not aware how that law is functioning and how much protection this Advocates Protection Law has given. (*Interruptions*) But I think, it is necessary to enact such law. At times, we also come across such news where lawyers are attacked, threatened or intimidated. Advocates need to practice fearlessly. After all, they are officers of the court.

They are important stakeholders in the administration of justice. I believe the suggestions given shall get the utmost attention of the Government.

The other part which I would like to mention is relating to regulating the academic or legal education. That needs to be strengthened. A large number of law colleges are being opened. But what is the quality of the lawyers? We all know that. The quality of the lawyers who are coming out from the law colleges is not only affecting the Bar but also affecting the Bench. But keeping that in mind, I think it is of greater need to look into these aspects also and to bring a comprehensive law in favour of the advocates and our advocacy system.

Thank you.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, on behalf of the Nationalist Congress Party, I stand here to speak on the Advocates (Amendment) Bill listed today.

Sir, Meghwal ji has been a colleague of all of us. He has been a pleasurable colleague for a long time. He is the colleague who brought in the Womens Reservation Bill. He is really lucky that he has brought in that Bill. Though it is not implemented, but in his legacy that he will leave behind, he will be known as one of the finest Ministers who has brought something which is very close to our hearts. I am not taking away the intent of this Bill which he has brought in.

I have only a few suggestions. I am not a lawyer. Most of the lawyers have spoken before me. But the intent of the Government, I am sure, is very clear about what they want to do. But I have a few suggestions and questions to ask them regarding the implementation of this Bill which is really a small Bill. But there are a few questions that I would like to ask the hon. Minister out of my lack of legal knowledge. He was asking what was a tout. Now, Mahtab ji has spoken about it and so also Shri Raja from the DMK. But I seek a clarification from the hon. Minister. About this, Mahtab ji has already read it out. He says that a tout is a person who procures in consideration of any remuneration. So, it is a one-sided thing. You see, in the Corruption Act, both the parties are considered to be making a mistake. Here you are only considering one party to it. So, should we not make it broader? We should make it whoever engages or whoever hires, both ways. I think the practice is wrong. So, why should only half the party be punished? So, if you are really trying to remove touting completely, why do you not include both the parties? This is my question. So, you could kindly clarify on that.

The other question from me is this. Who are the members present at every meeting? There is no clarity on it. In Section 45A, it is written, the explanation is, majority of the members present at the meeting. Now, who will be the members? Who will decide what will happen at the meeting? Who will decide, with such a small thing, who is a tout and who will be taking the decision? There is no clarity about this.

This is like what Raja ji said. I am reiterating the point. But there are no objects in the Bill. It is probably a little lacking in drafting. It is a lawyers Bill which has such a poor drafting, because, unfortunately, the Bill has to have its objectives. So, there is no objective in this Bill. So, what is the real reason of getting this Bill passed? Again, I am not taking you away from the intention of the Government. I am sure the intention is there. But when you are doing something for the lawyers, is it not that drafting and implementation are most important? It is not just intent but life is beyond intent.

The other thing is about reforms about which Meghwal ji spoke. I have never dealt with lawyers in my whole life but in the last six months I am flooded with lawyers in my life, be it dealing with the Election Commission or the Supreme Court. There is a saying in Marathi. With your permission, I would like to say that. In Marathi, they say,

मराठी जैसा जो होशियार होता है न, वह कभी कोर्ट की सीढ़ी नहीं चढ़ता है। मैं होशियार नहीं हूं, अब मानना पड़ेगा कि मैं तो कोर्ट की सीढ़ी चढ़ चुकी हूं। There was no option. So, I had no option but to climb it. Clearly, when you go to a court, there are a lot of issues that are raised. The tout issue is also discussed but my whole point is, there are a lot of reforms required in the court. Justice delayed is justice denied. I do not want to go to that point. I know that is not in the purview of the Bill. But one major point is, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. This is what Martin Luther King had said. So, I think this has a very broader role. We really need to expand the object of this Bill. Whenever we get to meet young lawyers anywhere, they complain of one thing. You go to the States. It is like somebody from the YSR Congress, Jagan Mohan Reddy jis Party, said that they are giving Rs.5,000 a month to young lawyers.

In Kerala, they give Rs.2000. So, is there something to engage all these youngsters who are studying very hard to pass it? Is there any social program this Government has in mind, like most States are doing? That is my first question to this Government. Then, I want to reiterate the point about technology upgrade. I think with technology many things are happening now. Is the entire game for lawyers going to be changed in the next few years? How do they skill themselves better? I mean, this whole thing about colonialization is being discussed. It is a past good or bad I think it has not been that bad on it. So, let us not just criticize our history. The way forward is change, and change is inevitable in everybodys life, and that is what policies also do. Policies also will have to change with time. Look at the life today. Look at something like artificial intelligence. This is something we did not even expect. We did not even expect a mobile phone about 10 years ago in our life, which has changed our life. So, every profession is changing, and so are the lawyers. Is there something this Government has in mind for technology upgrade of all the lawyers?

The Advocates (Protection) Act which Mahtab ji talked about, I would like to take it a little forward. Many Governments all over the country are not just talking about advocates but are even talking about the safety and security of doctors and Press because I do realize that we all must put our minds together in this Government and in Parliament that there is somehow much anger in society nowadays. I do not know where this anger is coming from. Even in Maharashtra, we are having a lot of challenges in this regard. I am not trying to digress but I am just giving a small example. Please do not misunderstand what I am saying. There are a lot of agitations going on in Maharashtra today on reservations, be it Maratha, Lingayat, Muslim, etc. A lot of stone pelting is suddenly happening. So, there is clearly some anger breeding somewhere. You hear doctors getting beaten up, you hear threats like Mahtab ji said about lawyers, there are Press people who are getting beaten up. So, there is something missing somewhere. I think this House, the Parliament needs to discuss all the social issues because our intent is of changing peoples life for the better. That is why we get elected and come here. At policy level, the intent of the Government to bring in to removing of the touts is a very welcome step.

The only thing when I was hearing about touting, आपको भी याद होगा, उस समय मल्टी-प्लेक्सेज तो थे नहीं, तो टाउट्स खड़े होकर सिनेमा के टिकट्स बेचते थे। 10 रुपए का टिकट 100 रुपए में मिलता था। उस समय आई-पैड वगैरह नहीं था। That whole touting business is over because first-day-first-show life is over. So, technology does evolve life. It will probably eventually do remove touts. But till then, can we do something better,

simpler, positive? Like Meghwal ji and Raja ji said, I would like to reiterate their point, that why not bring a comprehensive Bill? Bring it, we can put it into the Law Ministry. The Law Minister is a very fine Minister. He is very supportive to all the demands of women that he did for us in the Womans Reservation Bill. I would request him to take this back, and let us take all the points suggested by all the renowned lawyers in the House, bring a more comprehensive Bill, take all the feedback, maybe send it to a Standing Committee, there are good lawyers who can help make it better. I think even the Environment Minister is also a lawyer, if I am not wrong. Maybe there would be some feedback from him as a lawyer. Have a more comprehensive Bill in the larger interest of the advocates in this country. Thank you, Sir.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Advocates (Amendment) Bill, 2023.

Sir, let me begin by quoting Mahatma Gandhi, who himself was a lawyer and an ardent champion of justice. An unjust law is itself a species of violence. Arrest for its breach is more so, states Gandhi ji. The quote means that any law must be aimed at delivering justice, and addressing the grievances, and if a law is unjust, arresting someone on the basis of that law is a form of violence. So, the law has to be just to itself first, is the context of the Bill and my speech.

The Bill titled Advocates (Amendment) Bill, 2023 is aiming at the insertion of a new section, which is Section 45(A) in Section 45 of the Advocates Act, 1961, which grants power to frame and publish list of touts to every High Court, District Judge, Sessions Judge, District Magistrate and every Revenue Officer not being below the rank of a Collector of a district (each as regards their or his own court or the courts, if any, subordinate thereto). I have certain observations and recommendations in this regard which are as follows.As per the law, the authorities empowered to frame and publish a list of touts as provided under Section 45A should be confined to only judicial authorities and not executive Magistrates. If the District Magistrates are given such power to frame rules, we cannot ensure transparency in finding out actual touts as defined under Section 45(7)(d) of the Amendment Bill. Similarly, the offence under the Amendment Bill as provided under Section 45(6) may be a cognizable offence and the penalty should be enhanced to a minimum imprisonment of one year and fine to at least Rs. 10,000. Or else, no purpose would be served. Apart from these suggestions, Hon. Chairperson, Sir, through you, I would like to ask the Government who is a tout and what benchmarks they will use to identify a person as a tout. It is absolutely agreed that touts are a menace to the courts, and the justice system, but what about people who would be implicated as touts, where an excessive power is given to the courts? Any innocent person could be branded as a tout and that will be a dangerous situation. The question here is that we live in a highly polarised nation, divided by hatred, intolerance and discrimination. In this scenario, if excessive powers are given to the officers of the court to determine a tout, anyone could be expelled and stopped from coming to the court premises. For example, a Dalit could be branded as a tout, just because he is a Dalit, by an officer belonging to an upper caste who harbours a discriminatory behaviour towards Dalits or other communities.

Another aspect is that the Amendment Bill does not take into account any standard procedure for fixing the modes of appeal, for a person branded as a tout, other than a simple appeal. This mechanism is problematic at many levels as the appeal system on many occasions is found to be biased. Therefore, I demand that the Appeal Committee must consist of representatives of SC/ST community so that communal representation is ensured. I hope, the hon. Minister will agree to my suggestion. I would also like to add that there are many issues concerning the legal system, including the reservation for SC and ST in appointment of judges in the higher courts, which has been a long-standing demand for many decades. I would like to appreciate the hon. Minister, Shri Arjun Meghwal ji, who has taken the charge of this Ministry. He always stands for and fights the cause of untouchable people. In the Law Ministry, during his tenure, he has to take so many actions for ensuring the representation of the SC/ST in the Indian judiciary. I also demand that the young advocates belonging to the SC/ST community must be given necessary stipend and financial support during their practice because as juniors, they are finding it difficult to survive in the present conditions.

Then, I would like to bring to the notice of the hon. Law Minister another important demand, that is, the demand for establishment of more benches of High Courts. In various States, there is a demand for the establishment of High Court benches. In Kerala also, there is a long pending demand to set up a High Court bench in Thiruvananthapuram. So, I would like to request the hon. Minister to consider this long pending demand of Kerala. Furthermore, I would like to conclude by saying that the amendment aiming to identify

and expose touts must not become a tool for opposition of any individual and it must be implemented in a just and fair manner.

With these words, once again, I congratulate hon. Minister Shri Arjun Meghwal ji as the Law Minister of this country for having brought this important legislation.

Thank you very much

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

16.25 hrs

(Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair)*

मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ । मैं चाहता हूँ कि सभी माननीय सदस्य इसको सर्वसम्मति से पास करें । मैं माननीय मेघवाल साहब को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस बिल को लेकर आए हैं । इसमें दो आस्पेक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं । एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट है, वह 1879 का है । ऑलमोस्ट उसके सारे प्रावधान एडवोकेट्स एक्ट में ले लिए गए हैं और वे एडवोकेट्स एक्ट के द्वारा ही गवर्न होते हैं । सिर्फ एक प्रावधान जो रहा है, वह टाउट्स का रहा है । उस प्रोविजन को, जो उसका सैक्शन 36 है, सिर्फ टाउट्स के लिए हमें लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879 को देखना पड़ता है । वह प्री-इंडिपेन्डेन्स टाइम का बना हुआ है, कोलोनियल टाइम का बना हुआ है । हम टाउट्स की परिभाषा और टाउट्स के प्रोविजन को देखने के लिए लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879 को देखते हैं, जबकि एडवोकेट्स एक्ट में दूसरी सारी की सारी चीजें, जो लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करने की बातें हैं, वे आ चुकी हैं । इसलिए वह जो पूरी की पूरी परिभाषा है और उसके प्रावधान सैक्शन 45(ए) एडवोकेट्स एक्ट में इनकॉरपोरेट करके बहुत अच्छा किया है । इसके लिए मैं माननीय मंत्री मेघवाल जी को धन्यवाद देता हूँ । जब वह प्रोविजन इसमें इनकॉरपोरेट हो जाएगा और यह लागू हो जाएगा, उसी समय जो एक कालोनियल एरा का लॉ है, जो लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879 है, वह लॉ खत्म हो जाएगा, वह रिपील हो जाएगा । इसका भी प्रोविजन इसके साथ में दिया है । दूसरा आस्पेक्ट टाउट्स का है । आप देखिए कि लीगल प्रोफेशन में यह बहुत बड़ा स्टिग्मा है । दूसरे बिजनेसेज में ये दलाल हो सकते हैं, लेकिन लीगल प्रोफेशन में दलाल की कोई जगह नहीं है । इसलिए एडवोकेट्स एक्ट में भी यह प्रावधान किया गया है । चाहे हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल हो, चाहे एडवोकेट्स की एसोसिएशन हो, लीगल प्रैक्टिशनर्स की एसोसिएशन हो, लीगल फ्रेटरनिटी के सब लोग यह मानते हैं कि इस प्रोफेशन में जो इस तरह के टाउट्स हैं, वे इसमें नहीं होने चाहिए । यह एक बहुत ही अलग तरह का प्रोफेशन है । इससे सबसे ज्यादा तकलीफ में समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति आते हैं, जो इनोसेंट हैं, जो जानते नहीं हैं। चाहे किसान हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के लोग हों, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को पता नहीं होता है और वे इस तरह के टाउट्स के चक्कर में आ जाते हैं । इस वजह से उनके ज्यादा पैसे खर्च होते हैं । एक तरफ आप देखेंगे कि चाहे कारपोरेट्स हों, चाहे बड़े-बड़े बिजनेस हों, चाहे बड़े पढ़े-लिखे लोग हों, वे लोग चिन्हित कर लेते हैं कि कौन से वकील को करना है और कौन से वकील को नहीं करना है । उनको इस तरह की परेशानी नहीं आती है । टाउट्स की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी गरीब लोगों को आती है । यह बहुत बड़ा कदम मोदी सरकार के द्वारा लिया गया है । मैं पुन: मेघवाल जी को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस तरह की परिभाषा को एडवोकेट्स एक्ट, 1961 में लाए हैं, स्वतंत्रता के बाद में यह एक्ट पास हुआ है और कोलोनियल टाइम के कानून को खत्म करके, उसे पूरा का पूरा रिपील करके इसमें लाए हैं ।

महोदय, इस वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लीविंग के लिए प्रधान मंत्री जी का जो विजन है, वह भी पूरा होता है और सबसे बड़ी बात है कि गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा था, वह भी खत्म होगा । आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा विकटिम्स ग्रामीण जगहों के लोग होते हैं । वे इनोसेंट होते हैं, कमजोर होते हैं और गरीब होते हैं। जब वे शहर आते हैं और वकील नियुक्त करते हैं तो उन्हें मिस गाइड किया जाता है और खर्च का सारा भार उस गरीब पर पड़ता है । यह कानून ऐसे गरीब पीड़ितों को लाभ देने के लिए लाया गया है । इसमें तीन लोग इनवॉल्व होते हैं । एक लिटिगेंट होता है जो पुअर और इनोसेंट होता है । दूसरा पर्सन एडवोकेट भी हो सकता है और कोई दूसरा भी हो सकता है, जो कि वकील करवाने के बदले दलाली लेता है । यह समस्या भी आती है कि ज्यादा दलाली लेने के लिए क्वालिटी लॉयर भी नहीं करवा कर देते हैं जिसकी वजह से अच्छी सर्विस न मिलने की वजह से पीड़ित को न्याय भी नहीं मिलता है । लिटिगेंट को पता नहीं होता कि वह दलाल है और मदद करने की एवज में दलाल को पैसे देता है । दलाल को आइडेंटिफाई करने का तरीका होना चाहिए । जिसने कंसिड्रेशन दिया और जिसने कंसिड्रेशन लिया, वे तो पीड़ित नहीं हो सकते हैं । एग्रीव्ड सिर्फ इनोसेंट होता है । एग्रीव्ड को पता नहीं होता है कि इसके खिलाफ शिकायत भी हो सकती है या उनके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है । जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है ।

चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हों, सैशन कोर्ट्स हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों, रेवेन्यू कोर्ट्स हों या ट्रिब्यूनल्स हों, हालांकि इस बिल में ट्रिब्यूनल्स शब्द का यूज नहीं किया है, लेकिन मेरा मानना है कि चाहे किसी भी तरह की कोर्ट्स हों, ये वहां नहीं होने चाहिए । ये लोग रेलवे स्टेशन्स पर मिलेंगे, बस स्टैंड पर भी होंगे और दूसरे पब्लिक प्लेसेज पर भी होंगे । ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए यह कानून लाया गया है, इसके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन जो लिस्ट बनती है, उसके लिए एविडेंस गैदर करना हरक्यूलियन टास्क है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस एक्ट में जो रूल बने, उसमें एम्पल प्रोविजन ऐसे हों जिनमें इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि इनोसेंट की हम कैसे हैल्प कर सकें, इसके लिए एक्ट में किस तरह के रूल फ्रेम करें, यह जरूर स्पष्ट होना चाहिए । दलालों की लिस्ट पब्लिश होने के बाद कांसिक्वेंशल इफेक्ट दो हैं । एक इफेक्ट तो यह होगा कि वह उस न्यायालय में उपस्थित नहीं रह सकता है, लेकिन वह कहीं ओर से ऑपरेट कर सकता है । दूसरा कांसिक्वेंशल इफेक्ट पांच सौ रुपये पैनल्टी की पनिशमेंट का है और जेल का भी प्रावधान है जोकि बहुत कम है । इस तरह से हम क्राइम को रोक नहीं सकते हैं और आज की तारीख में उससे पांच सौ रुपये जुर्माना लेना बहुत कम अमाउंट है । इसके अलावा पनिशेबल इम्प्रीजमेंट तीन महीने तक बढ़ाने का प्रावधान है और विद फाइन या दोनों भी हो सकते हैं ।

अगर किसी लेवल पर सिर्फ फाइन ही इम्पोज़ करें तो 500 रुपये फाइन होंगे, लेकिन इन्नोसेंट व्यक्ति के साथ चीटिंग होगी । यह हो सकता है कि वह उसका केस भी खराब कर दे । इसलिए, इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने के लिए समुचित प्रावधान इसके रूल्स में आ जाए, जिससे गरीबों को फायदा मिले । माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह एक ऐसा विजनरी कदम है, जो गरीबों को न्याय मिलने में आ रही बाधाओं को हटाएगा । इन्नोसेंट लोग, चाहे वे गरीब हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों, चाहे गांव के किसान हों, उन लोगों के साथ धोखाधड़ी न हो, इसके लिए यह कानून है । महोदय, मैं पुन: माननीय मंत्री जी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप यह कानून लेकर आए हैं ।

श्री मलूक नागर (बिजनौर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

महोदय, इस एडवोकेट्स (अमेंडमेंट) एक्ट, 1961 में टाउट्स की जो बात हो रही थी तो पहले यह सोचना पड़ेगा कि उनके लिए क्या शब्द दें । कानून का पालन कराने के लिए गैर कानूनी तरीके से अगर कोई धन कमाता है तो उसे बिचौलिया कहें, दलाल कहें या जो भी कहें, उसको रिमूव करने की बात और लोगों को ठगने से बचाने की जो बात इस अमेंडमेंट बिल में आई है, इसका हम समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं । यह एक अच्छी पहल है । जैसा कि हमारे साथी बोल रहे थे कि इसमें जो सफरर हैं, वे इन्नोसेंट लोग हैं । इसमें अगर ज्यादा सख्ती की गयी तो वे तो न्याय से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा । इसलिए, मैं इसके साथ-साथ माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि एक ऐसी व्यवस्था करें कि उसमें जो गरीब लोग हैं, जो बहुत दबे-कुचले लोग हैं, जो एस.सी./एस.टी. के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए कोर्ट में ऐसा कोई कमरा बने या ऐसी कोई व्यवस्था बने जहां जाकर अगर वे कुछ जानकारी लेना चाहें, कोई सुविधा लेना चाहें तो वे ले सकें । उसमें बार काउंसिल के लोगों को कुछ पावर्स दें । उसमें वहां के लोग हों और राजनीतिक रूप से अलग से भी लोगों को डिप्यूट करें, जो वहां मौजूद रहें और जो उनकी काउंसलिंग कर सकें और उन्हें सही रास्ता दिखा सकें, जिससे उनका धन खर्च न हो, उनके साथ ठगी भी न हो और उन्हें न्याय मिले ।

महोदय, जब बात कानून की हो रही है, तो इसी से संबंधित मैं एक बात और कहना चाहता हूं । पिछले दिनों कोरोना महामारी हुई । कोरोना के समय में जो वकील थे, वे उस समय दूसरा कोई प्रोफेशन कर नहीं सकते थे । इसलिए अगर कोई महामारी या इस तरह की स्थिति आ जाए तो उस समय सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे, जिससे वकीलों को भी दूसरा कोई काम करने का मौका मिले या उनके लिए ऐसी कोई कंटीन्जेंसी फीस की व्यवस्था की जाए ।

महोदय, हमारे लॉ एण्ड जस्टिस कमेटी में भूपेन्द्र यादव जी रहे हैं । उन्होंने उसमें बहुत मीटिंग्स की । हमें भी उसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लीगल एजुकेशन में हमारा देश कहां खड़ा है, उसमें सरकार यह इवैल्यूएट करे । अगर हम अपने देश के संस्थानों की वर्ल्डवाइड रैंकिंग निकालें तो उसमें केवल आई.आई.एम., अहमदाबाद 551वें स्थान पर आता है । बाकी जितनी भी बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं, वे 25,000 की रैंकिंग के बाद आती हैं । विश्व के पैमाने पर, जो यू.सी.एल. है, जहां से महात्मा गांधी और रविन्द्र नाथ टैगोर पास-आउट हैं, वह रैंकिंग 4 पर है । रैंकिंग 5 पर एल.एस.सी. है, जहां से बाबा साहेब अम्बेडकर पास-आउट हैं । ऐसी ही आईवी लीग है, जिसमें सात टॉप यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर एक लीग बनाई कि हम रैंकिंग 1 पर हैं । इसी तरह, जो लीगल एजुकेशन है, जिसमें सरकार और बार काउंसिल का हस्तक्षेप है, तो सरकार इस तरफ भी ध्यान दे कि इस सिस्टम को हम कैसे इम्प्रूव करें । हम देखते हैं कि हमारी स्टैण्डिंग कमेटी की मीटिंग में बार काउंसिल सरकार के ऊपर डालता है और सरकार के अधिकारी बार काउंसिल के ऊपर डालते हैं । इसमें भी सरकार ऐसा कोई प्रावधान करे, जिससे वहां इतनी पारदर्शिता हो जाए और हमारे देश का लीगल एजुकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव हो सके । चाहे वह मेडिएशन की बात हो, चाहे वह आर्बिट्रेशन की बात हो, हमारा देश आज तरक्की कर रहा है । वकीलों से संबंधित मामलों में भी हमारा देश उतनी ही तरक्की करे और हमारे देश के आर्बिट्रेशन सिस्टम से, मेडिएशन सिस्टम से और यहां की एडवोकेसी से पूरे विश्व में हमारे देश का एक नाम हो और जैसे पहले विदेशों में पढ़ कर लोग नामचीन बनते थे, उसी तरह अब भारत में पढ़ कर लोग पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो सकें ।

साहब, मैं अपनी बात समाप्त ही करने वाला हूँ । मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो यह टाउट्स की बात हो रही है, मान लीजिए कि वे जाँच के घेरे में आ गए और पकड़ लिए गए, तब उनको ऐसी सज़ा मिले, जिससे ऑटोमेटिकली आगे बंदिश लगे । मैं माननीय मंत्री जी का

संज्ञान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि कुछ ऐसे वकील भी हैं, जिनके पास आप सिर्फ केस डिस्कस करने चले जाओ, वे ऐसी बातें करते हैं कि मैं यह काम यूं ही कर दूंगा और झूठे-सच्चे नोटिस, झूठे-सच्चे केस करने लग जाते हैं तो ऐसी भी एक व्यवस्था सरकार सोचे, मंत्री जी सोचें कि उनकी जाँच हो कि इस वकील ने पिछले 100 केसेज़ कैसे किए हैं । क्या उन सब में झूठे ही केस हैं, उनकी एक लिस्ट बने और वह लिस्ट वेबसाइट पर होनी चाहिए, जिसको देख कर लोगों को यह निर्णय करने में आसानी हो कि किस वकील के पास जाना है और किसके पास नहीं जाना है ।

साहब, जो गांव-देहात के लोग हैं, जहां पर इंटरनेट और नेटवर्किंग नहीं है, वहां इंटरनेट और नेटवर्किंग के कनेक्शन, चाहे वह टेलिफोन से संबंधित सरकारी विभाग हो, चाहे प्राइवेट सैक्टर के लोग हों, वे इस पर भी पूरा ध्यान दें ।

साहब, मैं जहां से जीत कर आता हूँ, उस पश्चिम उत्तर प्रदेश से राजेंद्र अग्रवाल जी और बागपत के सत्यपाल जी भी आते हैं । जब चुनाव होते हैं, तब उस क्षेत्र के 27 एमपीज़ और 141 एमएलएज़ की सीट्स के सभी कैंडिटेड्स यह कहते हैं कि हमें जिता दो और हम यह मांग करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की एक बेंच की स्थापना की जाए । मैं आज आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जाए, जिससे वहां की मेरठ, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, कैराना, अमरोहा, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर लोक सभा की सीटों के क्षेत्रों को फायदा मिल सके । सरकार इस तरफ ध्यान दे ताकि जल्द से जल्द पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह काम हो सके क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रदेश के लोग कई 100 किलोमीटर का सफर तय कर इलाहबाद हाई कोर्ट जाते हैं । वहां तक जाने में कभी-कभी पूरा रात और दिन का सफर हो जाता है । सुविधाएं भी नहीं होती हैं, कभी ट्रेनों की टिकटें नहीं मिलती हैं इत्यादि लोग बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं । मेरी सरकार से मांग है कि पश्चिमी उत्तर के मेरठ क्षेत्र में हाई कोर्ट की एक बेंच की स्थापना की जाए ।

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Sir, thank you for allowing me to participate in the discussion on the Advocates (Amendment) Bill, 2023. The problem is identified in the Act. It has plagued the educational system for the last more than 100 years. The first attempt was made in 1879 to provide some kind of response to the problems. While I stand in support of the Bill, at the same time, I have reservations about the efficacy of the mechanism devised in the Bill. I am sceptical about the results of the Bill and whether it will achieve the intended purpose.

Sir, subordinate courts are burdened with 50 million cases. About 50 million cases are pending in our subordinate courts. Which Authority has to identify who is a tout? Who has to go for that kind of an exercise? It is not that somebody will call somebody a tout or somebody will identify somebody or publish a list. A procedure is to be followed. Who is burdened with that? Who is saddled with that responsibility to prepare the list and identify the persons? It is High Court, District Judge, Sessions Judge, District Magistrate and Revenue Officer. They are already over-burdened. How can a District Judge or a Sessions Judge can embark on that exercise? They also have to see the cause list for the day and also to deal with other problems that afflict the system. There is a malice in the system. That is why, I am doubtful whether this mechanism devised will be able to achieve the target? It is true that there are a large number of touts, particularly in trial courts.

But the process, the exercise to publish, to prepare the list and allow the person who is affected by the list or is affected by the exercise, may be undertaken by a District Judge. He has to be given a right to respond to the allegations. So, how can a District Judge or a Subordinate Judge deal with the exercise or prepare the list? I think, it is doubtful whether this system will bear the results. The right thing would have been that we designate an authority in a District Court like in a High Court we have a Registrar, Vigilance Officer or a Vigilance Commissioner who deals with cases of misconduct against lawyers. In the same way, in every District Court we should have an authority to deal strictly with this problem and prepare the list and whatever exercise is to be done, to follow that exercise. So, this is one reservation about it. I have heard from other hon. Members that there is some kind of a misconception about the problem. The problem that is sought to be addressed is not about every tout; it is only the touts who operate from the court premises. This is because our gullible people, the people who visit our courts are mostly affected by the people who operate from the court premises. That is why clause 5 says that one of the punishments will be that a Judge will exclude a person whose name is found in the list from the court premises. The Sessions Judge or any other Judge who is presiding over that court can exclude his presence from the premises of the court. So, this is not targeted against all the touts in whatever colour they are and whatever costumes they wear. It is only restricted to the touts who operate from the court premises and one of the punishments proposed to be given is to exclude them from the premises. But while preparing this list, and fulfilling all the procedural requirements, the procedural due process, because a person cannot be declared as a tout unless and until he is given a reasonable opportunity, I do not think that the system devised under this Act is going to get the results that we target at.

Secondly, one of the targets is not only the gullible litigant, the litigant who comes to the court, visits the court for redressal of some grievance. It is also the junior lawyers because these touts mostly eat up the work that may be dealt with by the junior lawyers who are fresh entrants to the profession. So, this is one of the welcome steps. This will be just received with that kind of an enthusiasm by the junior lawyers who are freshers in the law courts. But at the same time, I would urge the hon. Minister to propose some kind of an amendment to the Advocates Act that provides for some honorarium or some support to the fresh entrants, the new entrants to the profession because those are tough years for a junior lawyer. The initial five years are very tough years for a junior lawyer. I had proposed a Private Members Bill for giving assistance to the advocates. I think, that would be a welcome step if that is done so that they get some kind of a relief. With that, with whatever I said about the mechanism and my reservations about the mechanism, it is a welcome step. There should be some kind of a second look on it so that instead of burdening the Sessions Judge or the Presiding Officers at the courts who are already overburdened, it will be better to have a designated officer like a Vigilance Commissioner as we have in courts, in a High Court a Vigilance Commissioner or a Registrar Vigilance Officer who is asked to exclusively deal with the problem and who completes the exercise. Then only he will be able to efficiently identify them and the objects of this Act will be achieved.

Thank you.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Thank you very much, Sir. This piece of legislation is like a *fait accompli* one. The Advocates Act of 1961 was based on certain authentic reports and recommendations of the Judicial Commissions.

The Act of 1961 covered all the issues raised in the parent Act and that is perfect. But unfortunately, this particular provision relating to touts was missed there. This is to fill up that. That is the scope of the Act. That is okay.

Hon. Chairperson, Sir, I would like to point out one thing. I heard the speeches made by other hon. Members. They are not only MPs but they are also eminent lawyers and legal luminaries. They were all sharing certain apprehensions. First, what is the procedure for identifying and listing the touts? The procedure which is stipulated in this Act is having a confusion. So, that is to be re-addressed. They were citing certain burning issues such as deterioration in the judicial system of our country. Similarly, there is a wide kind of a criticism that impartiality and independence of Indian Judiciary is diminishing like anything. That is also a point of concern.

Another point which has been raised by you also is about the lack of representation for the underprivileged sections -- SCs, STs and OBCs. There is no judicious competition in the higher judiciary as far as these marginalised sections are concerned. We all know that trustworthiness in the Judiciary should be adhered to strictly. All kinds of unfair practices should be curbed. That is also a truth. Transparency and ethical values should also be strictly adhered to. We have to ensure that there is no loophole in the existing structure which loses trustworthiness in the judicial system in our country.

Sir, we all know the responsibility of the lawyers. Section 1 of Chapter II of Part IV of Bar Council of India frames code of conduct and etiquettes of advocates and prescribes duties of advocates in courts. That is very clear. Code of conduct was laid down. That shows that lawyers should not take up any case where the client may have some wrong thinking. There should be a clarity on that aspect also. Similarly, unfair practices, wherever they are, should be curbed and discouraged. Not only that, the code of conduct also says that lawyers should not promote unauthorized practices, and they should also avoid advertisement and solicitation of work. That kind of canvassing also should not be there. That can also be treated as a bad practice.

Similarly, lawyers responsibilities have also been categorised. They have responsibilities towards courts to do justice. In that way also, relation with the judges is also a very important thing. In fact, lawyers profession is not just a normal profession, it is a very sacred profession. A lawyer is duty bound to educate his client not to have any kind of unfair practices. As far as judicial credibility, transparency, and accountability is concerned, the whole nation is worried about that. Any kind of lapse taking place is a worrisome kind of a thing. We have to address that also.

The relation between judges and lawyers is a very important thing. You know that the Bar, that is, advocates and Bench, that is, Judges, play an important role in the administration of justice. Judges

administer the law with the assistance of lawyers. The lawyers are the officers of the court. It is a very important thing. Unfortunately, there is some kind of a misunderstanding which is developing with certain judges and lawyers. That is also an unhealthy practice. That also may kindly be addressed.

Sir, towards the end, I would like to say one thing that there is a complicated situation. Judge is a very powerful position and is very important one as per our Constitution. But I want to make a submission for the loud thinking of this House. It is about the reappointment of the Judges. Judges, unfortunately, may have a hope that after retirement, the Government may give him some new appointment. Is it a healthy practice? If this kind of practice continues, will it not affect the transparency and accountability of the Judiciary? That is a point to be debated as far as India is concerned now.

We all know the story of these appointments. I do not want to go into the depth of it. They should not have an impression that after retirement, if we do something for the Governments support, we may have better kind of appointment elsewhere. That kind of tendency is a bad tendency. That kind of tendency should not be encouraged and we have to think loudly whether we can give such kind of appointments to the Judges after retirement.

With these few words, I conclude.

Thank you very much.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के माननीय विधि मंत्री जी श्री अर्जुन लाल मेघवाल जी के प्रति भी आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं । आप एक से एक ऐसे कानून ला रहे हैं जिससे देश का सीधे-सीधे वास्ता है और उससे देश का कल्याण हो रहा है । इसके पहले आप नारी शक्ति वंदन कानून लाये, जिससे देश के नारियों में एक उत्साह का वातावरण जागृत हुआ और वह कानून के माध्यम से अपनी दिशा तलाशने का काम कर रही हैं ।

मैं अधिवक्ता संशोधन विधेयक, 2023 का हृदय की गहराइयों से समर्थन करता हूं । इस विधेयक को राज्य सभा में 1 अगस्त, 2023 को प्रस्तुत किया गया था । विधेयक का आशय सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए सभी अप्रचलित कानूनों या अपनी उपयोगिता खो चुके स्वतंत्रतापूर्व अधिनियमों को निरस्त करना, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करना और विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 को निरस्त करना है ।

कानून आज नहीं, बल्कि प्राचीन भारत में भी विधि व्यवस्था थी । जब उस समय यह कानून था, तब छोटे-छोटे समूह में रहने वाले लोग अपने समूहों के, जाति के मुखिया सभी सदस्यों के समक्ष खुले आसमान के सामने अपना निर्णय सुनाते थे । उस समय अलग-अलग तरीके से कठोर निर्णय देकर उनको दंडित करने का काम करते थे । उसके बाद जब राज सत्ता की स्थापना हुई तो राज्यालोक अपने धर्म गुरुओं और बुद्धिमान दरबारियों की मदद से न्याय देने का काम करते थे । यह लगातार चलते-चलते स्वतंत्रतापूर्व विधि व्यवस्था ब्रिटिश काल में भारत में एक मॉडल विधि प्रणाली विकसित की गई । ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 ने क्राउन लेटर्स पेन्टेंट द्वारा भारत में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया । इन लेटर्स पेटेंट ने उच्च न्यायालयों को अधिवक्ताओं और न्यायविदों के नामांकन हेतु नियम बनाने के लिए प्राधिकृत और सशक्त बनाने का काम किया ।

उसके आगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जस्टिस एस.आर.दास की अध्यक्षता में अखिल भारतीय बार समिति का गठन किया गया । समिति ने अपनी रिपोर्ट में अखिल भारतीय बार काउन्सिल और राज्यवार काउन्सिल की स्थापना करने की सिफारिश की । समिति ने बार काउन्सिल में अधिवक्ताओं के नामांकन, निलंबन या उसकी सदस्यता रद्द किए जाने की शक्तियों की सिफारिश की । समिति ने यह सिफारिश भी की कि गैर-स्नातक लीडर्स और मुख्तारों की आगे कोई भर्ती न की जाए ।

17.00 hrs

केंद्र सरकार ने वर्ष 1961 में अधिवक्ता अधिनियम लागू किया । यह अधिनियम भारत में लागू है । इस अधिनियम से भारत में विधि व्यवस्था के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया । इस अधिनियम में अखिल भारतीय स्तर पर विधि व्यवसाय की उपयोगिता और गरिमा कायम की गई है । अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि अधिनियम विधि व्यवसायों से संबंधित विधि में संशोधन करने के अतिरिक्त उसे समेकित भी करता है ।

महोदय, हम यहां दलालों की बात करते हैं । इस विधि व्यवसाय अधिनियम, 1879 की धारा 36 दलालों की सूची बनाने और प्रकाशित करने की शक्ति से संबंधित है । प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट तथा प्रत्येक राजस्व अधिकारी जो जिले के कलक्टर की श्रेणी से नीचे का न हो, प्रत्येक प्रेसीडेंसी को यह अधिकार दिया गया और उन दलालों के ऊपर कार्रवाई करने और आर्थिक दंडित या जेल भेजने का नियम भी बनाया गया है ।

सभापति जी, सदन में अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि सदन का दुरुपयोग किया जा रहा है । मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि सदन का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के 144 करोड़ लोगों के हित के लिए सदुपयोग किया जा रहा है ताकि कठोर और सही कानून बनाकर इसका लाभ मिल सके । भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सदन के माध्यम से, कानून के माध्यम से की जा रही है । अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि न्यायपालिका सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, मैं कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका किसी एक के लिए नहीं है, यह सबके लिए है । कानून की जानकारी होना सबके लिए आवश्यक है । कानून की जानकारी होगी तो कम से कम गलतियां होंगी और इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा । यह कानून दलालों के खिलाफ आया है, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को फिर से बधाई देता हूं, इससे दलालों पर अंकुश लगेगा, क्योंकि अब तो दलालों का ही बोलबाला है ।

मैं आपको अंत में बताना चाहता हूं कि मैं बिहार से आता हूं । बिहार में आज दारू और बालू का बोलबाला है । दलालों का बोलबाला वहां चल रहा है, सारी व्यवस्था में दारू बंद है, लेकिन दारू अभी भी चल रही है । हजारों लोग जहरीली दारू से मर गए लेकिन दारू आज भी बंद नहीं हो रही है । बालू की ओवरलोडिंग हो या चालान हो, दलालों के माध्यम से यह खुलेआम चल रहा है, इस पर अंकुश नहीं लग रहा है । हमें लगता है कि इस कानून के बनने से बिहार में भी दारू और बालू पर अंकुश लगेगा ।

महोदय, मैं इस बिल के लिए माननीय मोदी जी और माननीय कानून मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं । धन्यवाद ।

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Thank you, hon. Chairperson, for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Advocates (Amendment) Bill, 2023. On behalf of YSRCP, I fully support the Bill. I thank the hon. CM, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy and the floor leader, Shri Midhun Reddy for giving me this opportunity.

Self-respect and democracy are the basic essence for happiness of any human being. Money is secondary. Advocates play an essential role in this regard. An advocate with good heart can restore the self-respect of aggrieved citizens. They can bridge the gap between common man and justice. They can play an important role in building a society with equality. If they can support, the marginalised and under-privileged communities, they will be treated as living Gods.

The three basic responsibilities of any Government are justice, health and education. I hope this Amendment Bill will bring some relief to the common man of this country with regard to justice. We cannot deny the fact that justice is still a mirage to a large section of our society. Under the leadership of hon. Prime Minister, people are expecting more of such reforms in the Indian judiciary system.

Every kind-hearted citizen wants a change in the society. For a change in the society, amendments of the existing Acts should be a continuous process. So, this amendment is very much needed. It is need of the hour. The Advocates (Amendment) Bill, 2023 is proposed to amend the Advocates Act of 1961. This Bill repeals certain sections of Legal Practitioners Act of 1879 and consolidates the Act of 1961. The Bill provides that every High Court judge, district court judge, sessions court judge and District Collector may issue a show cause notice to a suspected tout, institute an enquiry and publish a list of the touts.

The courts can then prevent the listed touts from entering the court premises. The listed touts may be punished with imprisonment and are fined. These are welcome measures. Since tout in legal system is detrimental to a good society, this anti-touting law, if enforced strictly, can curb unethical legal practice in India. At this juncture, the Government should take care to avoid overlap of work of Justice Deepak Gupta Committee and this amendment.

Sir, since this is a very small Bill, I would like to take this opportunity to highlight a few more issues of the judiciary system. Amendment to various Acts related to legal system are needed for natural justice to prevail, for example, the advocates registry. The Bar Council of India website has a registry of advocates but it is not easy for the common man to access it. Advocates registry access through a smartphone app can be of immense help to the common man so that he can select an advocate with good credentials.

As far as the problem of junior advocates is concerned, they are in plenty, which need to be addressed. In the judiciary parlance, there is a word called syndrome of underpaid and over-worked junior advocates. First five years of any first-generation advocates life is pitiable. They are underpaid, sometimes as low as Rs. 5000. There is no time schedule and no work rule. So, their livelihood should be respected. This problem can be solved to some extent by a change in the curriculum of LLB course. Practical knowledge should be imparted along with theory. Internship courses need to be started by the Government. Some social security measures like health insurance, provident fund, and ESI should be given to the junior advocates. This will safeguard the existing practitioners and also attract the best talent in this profession. Judges and administrative staff of the judiciary system are better placed when compared to junior advocates. This anomaly needs to be corrected. Young members of the Bar are the future of the Bar. The standard of the Bar will remain good only if these young advocates are taken care of. With the evolution of society, good lawyers will be the need of the hour for both, the Bar as well as the Bench.

As far as the welfare committee of the Bar is concerned, a separate committee should be constituted as in many western countries which will take care of the financial, physiological, and health needs of the junior advocates. Some financial assistance should be given from the Bar Council to the junior advocates in need. The inefficient legal system should be taken care of. As per the data provided by the National Judicial Data Grid, 21 lakh civil cases and 61 criminal cases are pending in the courts of India. A junior advocate will lose faith of the client when the case is prolonged for many years. This has nothing to do with the efficiency of the advocate but it is the fault of the legal system. We talk about ethics of doctors, politicians, students, and professors but nobody talks about the ethics of judges in India. Can we make laws to fix a timeframe for disposal of litigation?

Enrolment fee by State Bar Councils lacks uniformity. For example, it is Rs. 750 in one State Bar Council and it is Rs. 15000 in Delhi State Bar Council. This is against Section 24(1)(f) of the Advocates Act of 1961 and violates the right to equality under Article 14. I request the hon. Minister of Law to take necessary steps in this regard. Sir, likewise, the budgetary allocation should be increased and low ratio of Judges to population should be taken care of.

Sir, at the end, I would like to mention about YSR Law Nestham. The Government of Andhra Pradesh under the able leadership of hon. Chief Minister Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy is providing a monthly stipend of Rs. 5000 to all junior advocates since December 2019. As usual, our beloved leader is a trend setter of many novel welfare schemes in India. I request the hon. Minister to start a similar scheme on all-India basis.

To conclude, Sir, the Advocates (Amendment) Bill, which seeks to reform the legal system in India, needs effective implementation.

With these words, I support the Bill.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Mr. Chairman Sir, for affording me this opportunity to take part in the discussion on the Advocates (Amendment) Bill, 2023. Though it is a small Bill, it is very important as far as the advocates community is concerned.

Sir, most of the hon. Members, especially Shri Jagdambika Pal ji, made eloquent speeches praising the hon. Prime Minister where they said that under the leadership of the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, wonderful things have been done by means of this legislation. I cannot understand what the spirit is and what the contents of this legislation are. Also, I am not sure about what Mr. Jagdambika Pal ji has imagined or assessed about this legislation. It is because this is a legislation which is already in existence. The only thing that the Government is doing is to repeal an obsolete law. Other than that, nothing is new in this Bill. Jagdambika Pal ji, everything is a colonial legislation. This itself is a colonial legislation. You are taking a portion of Section 36 of a colonial legislation and incorporating it in the Advocates Act. There is nothing new. No revolutionary thing is done by the hon. Prime Minister in having this legislation. Unfortunately, you are unnecessarily praising everything. The Act of 1961 is there. The Act of 1879 is also there. So, you have to understand that you took a portion of the 1879 Act and incorporated it in the 1961 Act. You are only repealing an obsolete law of 1879. That is the only thing which is happening. This is the way by which exaggeration is going on in this House regarding so many things which are being done by this Government.

Sir, I fully support this Bill but I would like to seek some clarifications from the hon. Law Minister. Number one, the Statement of Objects and Reasons in the Bill is not so specific. You are mentioning that it is only to repeal the obsolete law. But at the same time, you are incorporating some provision in that. Section 36 of the 1879 Act is being incorporated in the Advocates Act of 1961. As you are incorporating a new provision, that should also come in the Statement of Objects and Reasons. That is a simple observation as far as the Statement of Objects and Reasons is concerned.

Another point on which I would like to seek clarification from the hon. Law Minister is this. The Legal Practitioners Act 1879 was in existence. In order to replace the Legal Practitioners Act 1879, in the year 1961, a new Act, that is, the Advocates Act 1961 was made. But unfortunately, except Sections 1, 3 and 13, all other Sections were repealed. These Sections were there in the original Act of 1879. My question is this. In the year 1961, why did the then Legislature, the then Parliament avoid this provision of Section 36 from the 1961 Act? To my understanding, to my knowledge, it is because this has nothing to do with the advocates. Section 36 of the 1879 Act is relating to the touts. The Advocates Act is a law consolidating the rules and regulations relating to the advocate profession. The touts have nothing to do with that profession. That might be the reason due to which Section 36 was not incorporated in the Advocates Act 1961. So, I would like to seek the clarification or the justification from the hon. Minister that how the law relating to touts will come within the purview of the Advocates Act 1961. I am seeking that clarification from the hon. Law Minister. This is the point on which I would like to discuss as far as the contents of the Bill is concerned. Otherwise, the Bill is absolutely okay. We fully agree with the Bill because obsolete laws have to be repealed from the statute book. But the only clarification that I am seeking is this. How will the law of touts be relating to the law of advocates?

There are one or two other points to which I would like to draw the attention of the hon. Law Minister. Nowadays, in most of the legislations which are coming for enactment, advocates are being omitted or the role of the advocates is being limited by means of the legislation. The Government has to take care of that because nowadays, strict legal interpretation is very difficult. Even the Chief Justice of the hon. Supreme Court has already observed that it is very difficult to understand and interpret the verbatim or the legal drafting of the laws made by the Parliament.

At the same time, most of the times, we are trying to limit the role of the advocates in the legal proceedings and thereby so many authorities have been formed. In almost all the authorities I am not going to cite the examples the role of the advocates is being limited. That has to be looked into. That is one of the issues which I would like to highlight.

Most of the Members have spoken about it. The previous speaker also spoke about it. This is regarding the Advocates Act. We know that the Advocates Act is meant for regulating the profession along with the Bar Council which is also a part and parcel of this Act. So, we have to keep in mind the welfare of the advocates also. We know about the medical profession. In the medical profession and in almost all the other professions, like the internship allowance, so many other allowances are there. As far as the junior advocates are concerned, in Kerala, we have a phrase that there are four stages in the profession of an advocate. The first stage is the raw junior. There is no case and there is no fee. The second stage is, there is case but there is no fee. The third stage is, there is case as well as fee. And, the fourth stage is the super senior stage where there is no case but fee is there. These are the four stages of an advocate in the local language we are saying.

So, what is my point is that the junior advocates have to be protected by providing some internship or stipend allowance of not less than Rs.25,000 for pursuing their profession. Something has to be done because in house surgency internship and so many other things, we are providing such types of allowances. After PG degree medical examination, we are providing all these amenities. Similarly, the junior advocates have to be protected so that they will maintain the profession in a proper way.

In so many executive posts, the law degree has to be made compulsory. My suggestion is, as far as the Station House Officer is concerned, a Station House Officer has to be well aware of the law, especially the Criminal Procedure Code, the Indian Penal Code and the civil law. They have to be well versed in the law. But unfortunately, in most of the stations we know very well that the SHOs are not fully aware of this. So, as far as the SHOs are concerned, the minimum qualification of a Station House Officer should be that

they should have a legal degree, that is, an LLB degree. That should be made compulsory for all such types of executive posts.

The last point which I would like to highlight is this. As far as the medical profession is concerned, you know we have made the proposal for protecting them. A law is there. Sir, 22 State Legislative Assemblies have made laws for protecting them by providing safety and security to the medical professionals. The same thing is not happening in the case of advocates. They require protection from the police forces. In my State, Kerala, in Trivandrum and in Kollam Bars, and in the High Court also, so many conflicts have taken place because police is brutally attacking the advocates. The police is interfering in the advocacy profession, and no protection is being provided to them. In such a way, we have to think of giving safety and security in the discharge of their profession as an advocate, especially from the police forces. Now a series of incidents of violence are happening in various parts of the country. That has to be dealt with. For this also, the Government has to think of formulating some legislation so as to protect the interest, safety and security of the advocates in the discharge of their functions as a legal professional or an advocate.

With these suggestions and with these clarifications, I would like to support this Bill once again. Thank you very much, Sir.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, taking advantage of this discussion today, I am goaded to participate in this Bill under the nomenclature, the Advocates (Amendment) Bill, 2023.

Already, several Members have participated and made their valuable suggestions on this particular legislation.

17.19 hrs (Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)

The issue is that the legal profession has already undergone a long evolutionary process in our country. The legal profession has been in existence since the ancient times. Then, the Head of the Groups or the Tribes delivered justice under the open sky before all the members. There was no specialist like a lawyer during those days. When the kingship was established, the king delivered justice with the help of his Religious Head and wise courtiers.

During the British period, the model legal system was developed in India. The Indian High Courts Act, 1861 passed by the British Parliament enabled the Crown to establish High Courts in India by Letters Patent, and these Letters Patent authorised and empowered the High Courts to make rules for enrolment of Advocates and Attorneys. The All India Bar Committee was constituted under the chairmanship of Justice S.R. Das. The Committee recommended the establishment of an All-India Bar Council and State Bar Councils.

Sir, we must acknowledge the fact that the legal profession is an important limb of the machinery for the administration of justice. Without having a well-organized profession of law, the courts would not be in a position to administer justice effectively. Also, the judiciary still is being treated as the last resort of the affected people across the nation. Sometime I feel that common people are losing their reliance upon Legislature, upon Executive and gradually they are going to resort to the judiciary in order to address or redress their grievances and their problems. So, the legislation should ponder over this growing phenomenon insofar as our legal mechanism is concerned.

Sir, the issue is that the Government is intending to bring in this legislation with an intention which has been depicted by the Government in this Bill that the Government of India in consultation with the Bar Council of India has decided to repeal the Legal Practitioners Act, 1879, and to amend the Advocates Act, 1961 by incorporating the provision of Section 36 of the Legal Practitioners Act, 1879 in the Advocates Act, 1961 so as to reduce the number of superfluous enactments in the statute book. Therefore, according to the core contents of the legislative document, we did not have any substantial argument to oppose this Bill. But certainly, we must say that still the legal professional mechanism should be more streamlined, should be more strengthened. Sometimes, in our own experiences we are facing various kinds of hassles and intricacies in order to execute our political activities.

जब सियासत के चलते, राजनीति के चलते कोर्ट के दर्शन करने पड़ते हैं तो पता चलता है कि कोर्ट के अंदर का लफड़ा क्या है, कोर्ट के अंदर की समस्याएं कितनी हैं । कोर्ट में जब हम जैसे लोग, जो बाहर से किसी केस में इम्प्लिकेट

होकर कोर्ट में जाते हैं तो वकील और कोर्ट के दलाल हमें मुर्गा समझते हुए जितना हो सके, नोचने की कोशिश करते हैं । यह बिल्कुल सच है । लोग कहते हैं कि अगर शेर ने आप पर हमला किया तो 12 या 13 चोट लग सकती हैं, लेकिन अगर कोर्ट और पुलिस ने हमला किया तो आपको 18 से ज्यादा चोट लग सकती हैं । इसी के चलते हम अपने कानून मंत्री को यह सलाह देना चाहते हैं कि आप गरीबों की बात सोचते हुए, आम जनता की बात सोचते हुए इस लीगल एड प्रोसेस को और मजबूत कीजिए । Legal aid for poor and vulnerable people should be strengthened in a manner that the entire process could be helpful for them. That is why I thought it prudent to at least put forward some of the views of the common people. वकीलों के ये सारे मुद्दे हमारी कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, इनमें और सुधार लाना जरूरी है । वकीलों, टाउटों और बीच में यहां पर ज्यूडिशियरी के बारे में कोई टिप्पणी की गई थी तो मुझे लगता है कि इस तरीके की टिप्पणी करते समय हमें और सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ज्यूडिशियरी, एग्जिक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये हमारे संविधान में चेक एंड बैलेंस के हिसाब से देखते हैं । ज्यूडिशयरी कॉन्स्टीट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करती है तो ज्यूडिशियरी पर पूरा भरोसा रखते हुए हम सबको इस तरीके के कानून बनाने चाहिए कि ज्यूडिशियरी हम पर हस्तक्षेप न कर पाए ।

अगर हम इस तरह का चुस्त-दुरुस्त कानून बनाने में सक्षम रहे तो चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म, चेकमेटिंग मैकेनिज्म पर यह और ज्यादा असरदार होगा । यह जो विधेयक लाया गया है, इसका समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री जी को यह कहना चाहता हूँ कि गरीब लोगों के लिए लीगल प्रोसेस को, लीगल मैकेनिज्म को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त कीजिए । यह सलाह देते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ और इस बिल का समर्थन करता हूँ ।

*m20 श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): सभापति महोदय, यह जो बिल लाया गया है, इसमें सरकार की नीयत साफ है, लेकिन बिल अधूरा है । इस वजह से अधूरा है, क्योंकि इसमें जो टाउट की डेफिनेशन दी गई है, उसके अंतर्गत इस बिल के अंदर टाउट का मतलब है कि persons who procure clients for a legal practitioner in return of money. टाउट्स का मतलब दलाल हो सकता है, बिचौलिया हो सकता है या मिडिलमेन हो सकता है । इस बिल में इन दलालों को, इन टाउट्स को पेनेलाइज और पनिश करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया है ।

सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या हम सिर्फ इस बिल के जरिए ये जो दलाल हैं, टाउट्स हैं, उनके ऊपर ही एक्शन ले रहे हैं या वे दलाल किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर सवाल नहीं उठने चाहिए? क्या वह दलाल सिर्फ अपने क्लाइंट्स से पैसे खींचने वाला है? जिस एडवोकेट के लिए वह पैसे लेकर जा रहा है, उस एडवोकेट पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? इस बिल के अंदर इसके बारे में भी जवाब होना बहुत जरूरी है ।

सभापति महोदय, यकीनन यहां पर आज जो डेफिनेशन दी गई है कि ये टाउट्स कहां पर मिलते हैं तो आपने बताया है कि they frequent places such as precincts of civil or criminal courts. सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के अतराफ़ में ये दलाल होते हैं । ये रेवेन्यू ऑफिसेज़ के अंदर होते हैं । ये रेलवे स्टेशन पर होते हैं और ये ग्राहकों की तलाश करते हैं ।

सभापति महोदय, यह बहुत गलत है । ये टाउट्स आज हर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आपको मिलेंगे और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां कानून बनाए जाते हैं, शायद उसके अतराफ़ में भी ये टाउट्स आपको मिलते होंगे । क्या आज पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर टाउट्स नहीं हैं? अगर किसी को बेल लेनी है और यदि पुलिस वाला यह कहेगा कि मैं बेल का अपोज़ नहीं करने वाला हूँ तो यह भी एक टाउट है । गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के अंदर अधिकारी भी टाउट का रोल अदा कर रहे हैं, यह भी एक सच्चाई है । इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर आप एक ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं, चूँकि आज देशभर के जितने भी टाउट्स हैं, वे खुश होंगे, क्योंकि इसके पनिशमेंट के पैसे महज 500 रुपये हैं । मंत्री जी, इस सरकार ने 500 रुपये की कीमत 50 रुपये के बराबर लाकर रख दी है । आप दलालों को कह रहे हैं कि अगर आप पकड़े गए तो हम आपको 500 रुपये फाइन करेंगे । अगर आप दोबारा पकड़े गए तो तीन महीने की सजा मिलेगी ।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि ये दलाल किस लेवल पर काम करते हैं, कैसे गरीबों को लूटा जाता है? यकीनन इस पर फाइन बढ़ाने की जरूरत है । सभापति महोदय, मैं आपके जरिए मंत्री साहब से यह कहना चाहता हूँ कि आज से तीन साल पहले जब कोरोना आया था तो मेरे चुनावी क्षेत्र में छोटी-छोटी दुकान वाले, जो छुपकर अपना कारोबार कर रहे थे, उन पर प्रशासन ने एक लाख रुपये, दो लाख रुपये, तीन लाख रुपये का फाइन किया । जब मैंने उसमें हस्तक्षेप किया, लेबर कमीश्नर के सामने जाकर बैठा, आंदोलन किया तो तीन लाख रुपये का फाइन तीन हजार रुपये का हो गया । उन लोगों को राहत मिल गई, लेकिन मंत्री साहब मेरे ऊपर एक केस रजिस्टर किया गया कि मैं सरकारी काम में हस्तक्षेप कर रहा हूँ । जब मैं पिछले दो सालों से अदालत के चक्कर काट रहा हूँ तो मुझे यह अहसास होता है कि आज इस देश की अदालतों के अंदर अगर लाखों केसेस पेंडिंग हैं तो ऐसे केसेज पेंडिंग हैं । एक घंटे के अंदर यह केस अदालत के अंदर जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अधिकारी के अहंकार को मैंने ठेस पहुंचाई थी तो केस रजिस्टर किया गया । आज दो साल से मैं अदालत के चक्कर काट रहा हूँ ।

सभापति महोदय, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि आप कह रहे हैं कि लॉयर्स का प्रोफेशन बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत प्रोफेशन है, लेकिन जब यंग लॉयर्स आते हैं, एडवोकेट्स आते हैं तो उन्हें स्टाइपेंड मिलना चाहिए और इनके लिए भी मदद होनी चाहिए ।

सभापति महोदय, मैं लॉयर नहीं हूं । मंत्री साहब, मैं लॉयर नहीं हूं और न ही मेरे पास लॉ की डिग्री है, लेकिन मैंने पिछले दो सालों से बेंच ऑफ हाई कोर्ट, औरंगाबाद के अंदर एक पीआईएल फाइल की है । (व्यवधान) मैं सिर्फ आधा मिनट बोलना चाहता हूं ।

मैंने मेडिकल सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए एक जनहित याचिका फाइल की है । मैं बेंच ऑफ हाई कोर्ट, औरंगाबाद को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सिर्फ मुझे सुन कर ऐसे फैसले दिए हैं । मैंने वहां पर दो सालों से वकील नहीं लगाया है । अदालत ने मुझसे कहा कि आप वकील क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो मैंने कहा कि वकील कानूनी भाषा बोलेंगे । मैं दिल से बताना चाहता हूं कि हमारी मेडिकल सर्विसेज को कैसे इंप्रूव करना चाहिए । यह प्रोफेशन बहुत अच्छा है, बशर्ते इसके अंदर से दलाल, बिचौलिए और टाउट्स को हटाया जाना चाहिए । यकीनन, आप इस बिल को लेकर आइए, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाने की जरूरत है । हम इसका समर्थन करते हैं । धन्यवाद ।

*m21 श्री गिरिधारी यादव (बांका): सभापति महोदय, सरकार के द्वारा अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 लाया गया है, यह अच्छी बात है । यह समग्र रूप में लाया जाना चाहिए । यह बिल पार्ट में है । यदि यह बिल समग्र रूप में आता, पूरा आता, तो और अच्छा होता । आपने सिर्फ कहा है कि इसमें से टाउट को हटा देते हैं । यह अच्छी बात है । इसको हटा दीजिए । वकीलों की जो स्थिति वकालतखाने में है, उनके बैठने-रहने की जो व्यवस्था है, आप उनके बाथरूम्स को देखेंगे, तो पाएंगे कि वे सबसे खराब हालत में हैं । जो नए वकील ज्वाइन करते हैं, उनकी क्या स्थिति है? वे बीमार पड़ जाते हैं, तो उनके इलाज का कोई इंतेजाम नहीं है । आप पूरा बिल लाइए । जो जूनियर वकील, नए वकील ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा अंतर है । इस देश के सीनियर वकील के पास पैसा रखने की जगह नहीं है, लेकिन इस देश के जूनियर वकील को खाने का ठिकाना नहीं है । इन बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है?

मैं फीस के बारे में कहना चाहता हूं । कौन-सा वकील फीस क्या रखेगा? इस देश की गरीब जनता न्यायालयों में जाती है । वहां कोई रेट तय नहीं है । रेट जो उनके मन में आया, कोई कहता है कि हम 20 हजार रुपए लेंगे, कोई कहता है कि हम 30 हजार रुपए लेंगे, कोई कहता है कि हम एक लाख रुपए लेंगे, कोई कहता है कि हम इसका ठेका ले लेंगे । जब आप कोर्ट में जाएंगे, केस लड़ेंगे, गरीबों से बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस देश में न्यायालयों की क्या हालत है । आप अच्छा बिल लाये हैं । आप दलाल को हटाइए । दलालों को हटाया भी जाना चाहिए । हम लोग भी चाहते हैं कि वहां दलाल न हों । दलाल न्यायपालिका के अंदर भी हैं । यह आपको देखना पड़ेगा । जो जज और वकील के बीच कहीं-कहीं कोई कनाइवेंस है, आप उसको भी खत्म करें । उनके मुंशी के पास लाइसेंस है । आप उनको कैसे हटा देंगे? वहां बाहर से कोई नहीं आता है । वहीं जो वकील के मुंशी हैं और लोग हैं, उसको क्या करिएगा? आप किसी को दलाल कहिएगा तो उसे मुंशी अपना वकील बना लेगा, तो आप और हम क्या कर लेंगे? अब वह प्रैक्टिकल नहीं है ।

आप इस देश में बिल एसी चैम्बर में बनाते हैं । जिसने आपका बिल बनाया है, क्या उन्होंने कोर्ट में जाकर किसी गरीब से बात की है? जो जेल में है, उससे बात की है? बिना दलाल के काम कैसे होगा? मान लीजिए कि जेल में मेरा एक आदमी है । उसके घर में कोई नहीं है । उसको छुड़ाने के लिए कोई आदमी गया । आप उसको दलाल बना कर जेल में डाल दीजिएगा, तो उसे कौन छुड़ाएगा? उसके कुछ लोग दिल्ली-कोलकाता में हैं । आप कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाइए । आप पूरा बिल लाइए । आप उनको मदद दीजिए । जिसके परिवार में एक आदमी जेल गया, उसके घर में कोई महिला है, तो वह कैसे कोर्ट जाएगी? जेल में टिप्पा लेना है, तो जेल में टिप्पा लेने कौन जाएगा? आपको पता ही नहीं है कि जब जेल में उसका टिप्पा लेगा, तब वकालतनामा फाइल होगा । इस देश में वकालत का जो पेशा है, उसमें बड़ा पैसा है । वकील लोग देश में क्रांति लाते हैं । चाहे जार के खिलाफ क्रांति हुई हो या फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ हो, सभी में वकीलों का योगदान है ।

देश में जितने बड़े आजादी के नेता थे, चाहे वे नेहरू जी हों या गांधी जी हों, वे सारे पेशे से वकील थे । उन लोगों का कैरेक्टर था, उन लोगों ने देश में अपना योगदान दिया है । इसलिए अब जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति में सरकार अच्छा काम कर रही है । इसको और अच्छे तरीके से करिए । आप सभी पक्षों को सुनिए और रखिए । आप एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाइए । आप यह बिल पास करिए, लेकिन गरीबों की जो हालत है, जो वर्षों से केस में फंसे हुए हैं । हमारे यहां एक पटना, हाई कोर्ट है । वहां की आबादी 12 करोड़ है । आप वहां एक दूसरा हाई कोर्ट नहीं दे रहे हैं । आप छोटे-छोटे राज्यों को दो हाई कोर्ट्स दे रहे हैं । आप मध्य प्रदेश में तीन हाई कोर्ट्स दे रहे हैं । हमें मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट्स से आपत्ति नहीं है । आप बिहार में क्यों नहीं एक बेंच बनाते हैं? आपको बिहार से सख्त नफरत है । बिहार ने 39 सीट्स दी, पहले 31 सीट्स दी, लेकिन भारत की सरकार बिहार के साथ नाइंसाफी कर रही है । इसको बिहार की जनता देख रही है । आप वहां यह क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? आप आबादी के अनुसार यह बनाइए । हम लोग वर्षों से जेल में पड़े रहते हैं । एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं, तो छ: महीने में आता है । हम बेल फाइल करते हैं, तो पांच महीने में आता है । जजों की संख्या नहीं है । हम चाहते हैं कि आप एक ऐसा बिल लाइए कि आबादी के अनुकूल हमारे राज्यों में भी बेल हो । हमारे राज्यों में भी हाई कोर्ट का बेंच बने । आप यह नहीं बनाते हैं । क्योंकि आपको हमारे राज्य से केवल वोट लेना है, जात-पात करना है, हिन्दू-मुस्लिम करना है, आपको वोट मिल जाएगा । आप यहां आकर केवल महाराष्ट्र और गुजरात का विकास करिएगा । (व्यवधान) आपके हल्ले से हमें कोई चिंता नहीं है । (व्यवधान) आपके हल्ले से मुझ पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है । (व्यवधान) आपको बिहार की जनता बतायेगी । आने वाले चुनाव में आपका बिहार में क्या हश्र होगा, ये सब इन बातों को जानते हैं । (व्यवधान) आप समय से बिल नहीं लाते हैं । आप

हम लोगों के साथ एकदम नाइंसाफी करते हैं । इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार के साथ न्याय हो और बिहार में हाई कोर्ट की एक बेंच खोली जाए ।

इन्हीं बातों के साथ, मैं बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

*m22 SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Thank you Sir for giving me an opportunity to speak on this Bill. This Bill has been listed for business so many times, yet it never came up for discussion. इस सरकार में सिर्फ तारीख पर तारीख आती गई, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए ।

The Government has brought this Bill with a very noble objective, but it is a decade late. The 249 th Law Commission Report that made the recommendation of repealing the Legal Practitioners Act, 1879 was laid in October, 2014. Hence, it took this Government 10 years to adopt these recommendations. This Bill should have been brought much earlier. Even when the Government has adopted the recommendations, they have done it in a half-hearted manner. Though the learned Advocate and my senior Member, Kalyan da has already spoken from my Party, I would like to make some suggestions.

Firstly, the Government should have at least come out with some sort of awareness campaign about the practice of tout and it being illegal. Unfortunately, a common man who has a legal case to fight may not be able to identify a tout altogether and end-up paying hefty fees to him. क्योंकि उसको यह लगता है कि अगर इसके पास जाएंगे तो शायद मुझे जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाएगा । इस चीज पर एक क्लेरिटी होनी चाहिए ।

Secondly, the Government usually advocates to go digital. यह गवर्नमेंट हमेशा कहती है डिजिटल इंडिया, सब कुछ डिजिटल है । But what happened in this scenario? Why could the Government not make a single database where all courts could upload their tout lists? कोर्ट्स में टाउट लिस्ट को अपलोड कर देना चाहिए था । This would have helped to mitigate this practice at a larger level and would limit this practice at scale.

Thirdly, I beg this Government to make the judicial system more accessible and more inclusive. I am sure that the entire House would like to see a more robust and equitable justice system. The legal fees taken throughout the country is unregulated. On the one hand, there are a few lawyers who charge a very high amount of fees up to Rs. 50 lakh for a hearing whereas, on the other hand, the Members of the Legal Aid Cell are paid a marginal fees. In fact, the *per capita* spending by the Government on legal aid is one of the lowest in the world at just 75 paise. This is extremely concerning, and I would urge the Government to make the system more equitable for all of us.

As policy-makers, it is our responsibility to ensure that all the wheels of justice turn smoothly and fairly. Thank you, Sir.

*m23 श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): महोदय, आपने मुझे द एडवोकेट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं । मंत्री जी, सदन में यह बिल लाए हैं । It is a very small change. मंत्री महोदय इस सदन में बिल लाए हैं । Every single Member of the House has supported this Bill. सर, बहुत साधारण सा यह बिल है और यह चेंजेज बहुत सालों से अपेक्षित था । एडवोकेट्स जो अपने जिलों में काम करते हैं, वे हमसे बात करते हैं और उनसे हमारी डिस्कशन होती है । मेरे क्षेत्र में एक ट्राइबल क्षेत्र पड़ता है । मेलघाट से जब एक-आध किसान आता है या एक्सीडेंटल केस होता है या फॉरेस्ट के साथ फार्मर्स की लैंड से संबंधित कोई केस होता है या आपसी फैमिली की प्रॉब्लम्स में वह किसान प्लेन पट्टे पर आकर कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाने के बाद, चूंकि वह इतना अनएजुकेटेड है कि उसे हर चीज समझाना बहुत मुश्किल होता है । तब उनके ट्रैपिंग का मामला आता है, उसमें कोर्ट के गेट पर पहुंचते ही उसे ट्रैप कर लेते हैं । किसान के जो लैंड के केसेज होते हैं, जो एक्सीडेंटल केसेज होते हैं, तीसरी पीढ़ी आने तक वे सॉल्व नहीं होते हैं । उसके केस का निर्णय जब लगेगा तब लगेगा, लेकिन इसके कारण उनके पास जो एकाध एकड़ जमीन रहती है, उसे भी बेचने की बारी आ जाती है । तब तक उसका कोई निर्णय नहीं लगता है और उसको तारीख पर तारीख दिलाने वाला जो मेडिएटर या दलाल गेट पर बैठा रहता है, वह उनको जाते ही ट्रैप कर लेता है । उसे हटाने का जो यह बिल लाया गया है, वह द बेस्ट है । जब एक नया एडवोकेट कोर्ट में आता है, तो उसे सोशल सम्पर्क बनाने में दो-ढ़ाई साल का समय लग जाता है । एडवोकेट्स को जितने पैसे जाते हैं, उससे भी ज्यादा बिचौलिए उनसे ले लेते हैं । इसमें गरीब, आदिवासी परिवार के लोग जो अपना केस लेकर जाते हैं, किसान के जो पानधान रास्ते होते हैं, मराठी में पानधान कहते हैं, मुझे लगता है कि उसे पगड़ी रास्ता भी कहते हैं । उस रास्ते पर जो वाद होते हैं, वे सालों तक चलते हैं । इसमें किसान की खेती बिक जाती है, लेकिन बिचौलिया निर्णय नहीं लगने देता है । इसे हटाकर डायरेक्ट्ली, जिसकी गरीब वर्ग को ज्यादा आवश्यकता है, ऐसे किसानों को, ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इससे बहुत फायदा होगा ।

सर, एक और प्रॉब्लम देखी गई है । जब हमने सभी एडवोकेट्स से बात की and asked as to what the problems were that they find when these poor and needy people come to them. They said that they cannot help them in

any which way. I asked them why they cannot help them. तो उन्होंने साफ कहा कि अगर हमारी मंशा भी रहती है, यदि कोई गरीब महिला अपनी फैमिली का कोई इश्यू लेकर कोर्ट में आती है या एक्सीडेंट में किसी का हसबेंड गुजर जाता है, तो उनको इंश्योरेंस के पैसे मिलने चाहिए । उसके लिए यदि डायरेक्ट मदद करनी है, लेकिन बिचौलिया पहले ही आकर बोल देता है कि एडवोकेट साहब इनकी मदद नहीं करनी है । आप जो अपने पैसे चार्ज करते हैं, आप उससे बढ़ाकर चार्ज करना । उदाहरण के लिए, यदि उसमें 50 रुपए मेरे हैं, तो आपको डेढ़ सौ रुपए चार्ज करने हैं । उससे कम चार्ज नहीं करना है । So, the advocate also becomes helpless. पीड़ित परिवार के साथ बिचौलिया इतना फैमिलियर हो जाता है कि अगर एक्सीडेंट में हसबेंड गुजर जाता है या कोई डिवोर्स का केस चलता है, तो वह इतना फैमिलियर हो जाता है कि जब फीमेल पर्सन के पास देने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, तो वह बिचौलिया उसका मिसयूज करता है । इसलिए यह अमेंडमेंट लाकर, मुझे लगता है कि ऐसे परिवारों, किसानों और जरूरतमंद लोगों की, जिनके केसेज कोर्ट में चल रहे हैं, उनकी मदद होगी । ऐसे बिचौलियों के कारण डायरेक्ट्ली गरीब लोगों को बहुत नुकसान होता है । इसलिए इस बिल को लाकर मंत्री महोदय ऐसे लोगों को डायरेक्ट्ली फायदा पहुंचा रहे हैं । मैं इसके लिए आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ । We support this Bill.

*m24 श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ ।

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करता है । आज जब इस विधेयक पर चर्चा हो रही है, लगभग हम सभी इससे सहमत हैं, तो एक समसामयिक चार लाइनों का कोरस मेरे ध्यान में आता है, जिसे मैं यहाँ कहना चाहूंगा ।

हो गये हैं सब स्वप्न साकार, कैसे मान लें हम,

टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान लें हम,

वेश-वाणी, तत्व-दर्शन दूसरों का यह सभी ले,

विकृतियों को ग्रहण करते, निज प्रकृति को आज भूले,

दूसरों की यह नकल है, अस्मिता क्या मान लें हम,

इस पराए तंत्र को निज तंत्र कैसे मान लें हम,

देश के भवितव्य को ही अब चुनौती मान लें हम,

हो गये हैं सब स्वप्न साकार, कैसे मान लें हम ।

जितने भी संशोधन, परिवर्तन आदि होते हैं और आज भी जो संशोधन लाया गया है, इस देश में ऐसे कानून, जिसमें परिवर्तन करना है, संशोधन करना है, इस काम का बीड़ा देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी की स रकार और हमारे सम्माननीय विधि मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने उठाया है ।

यह विधेयक, जो कानून व्यवसायी अधिनियम, 1879 के तहत दलालों से संबंधित कुछ धाराओं को निरस्त करता है । 1961 का अधिनियम कानून को समेकित करता है । कानूनी व्यवसायियों से संबंधित यह विधेयक बार काउंसिल और अखिल भारतीय बार का गठन करता है । विधेयक की मुख्य विशेषताओं में यह शामिल है । विधेयक में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी, जिसमें यह कहा गया है कि जिला कलेक्टर पद से नीचे नहीं है, ऐसे दलालों की सूची बनाकर प्रकाशित कर सकते हैं ।

महोदय, ये जो दलाल हैं, एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है, जो या तो किसी को भुगतान के बदले कानूनी व्यवस्था में कानूनी और व्यवसाय के रोजगार की प्राप्ति का प्रस्ताव करता है ।

महोदय, नागरिक या आपराधिक अदालतों के परिसर जैसे स्थान पर, जैसे राजस्व कार्यालय हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे स्टेशनों और ऐसी जगहों में रोजगार प्राप्त करने, न्यायालयों में न्यायाधीश किसी भी ऐसे व्यक्ति को न्यायालय परिसर से बाहर कर सकता है, जिसका नाम दलालों की सूची में शामिल है ।

महोदय, सूचियां तैयार करना, दलालों की सूची तैयार करने और प्रकाशित करने का अधिकार रखने वाले प्राधिकारी अधिनस्थ अदालतों को कथित या दलाल होने के संदेह वाले व्यक्तियों के आचरण की जांच करने का आदेश दे सकते हैं । एक बार जब ऐसा व्यक्ति दलाल साबित हो जाता है, तो उसका नाम प्राधिकारी द्वारा दलालों की सूची में शामिल किया जा सकता है । किसी भी व्यक्ति को शामिल किए जाने के विरुद्ध और बताने का अवसर प्राप्त किए बिना यानी लांछन से बचाने के लिए ऐसी सूचियों में शामिल नहीं किया जाएगा ।

महोदय, इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है, दंड का भी प्रावधान है और इस प्रकार से जो भी व्यक्ति दलाल के रूप में कार्य करता है, जबकि उसका नाम दलालों की सूची में शामिल है, उसे तीन महीने की कैद और 500 रुपए के जुर्माने तक का जो यह प्रावधान है, दंडित करने का जो प्रावधान है, यह वास्तव में बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही सोच-समझकर किया गया प्रावधान है । मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं ।

महोदय, पारदर्शी न्याय मिलना चाहिए । जैसा कि कहा गया है, न्याय मिलने के साथ-साथ न्याय मिलते हुए प्रतीत भी होना चाहिए । पवित्रता, सुचिता आवश्यक है । इसके लिए यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं और इसका समर्थन करता हूं ।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*m25 श्री अर्जुन राम मेघवाल: चेयरमैन सर, आपने आज यह चर्चा प्रारंभ करने की अनुमति दी थी । यह बिल The Advocates (Amendment) Bill, 2023, as passed by Rajya Sabha है. यह एडवोकेट एक्ट, 1961 है । आपने ठीक कहा, वही बिल है । 3 अगस्त, 2023 को राज्य सभा ने इसको पास किया था । आज यह हाउस लोक सभा इस बिल पर चर्चा भी कर रहा है और मुझे लगता है कि सर्व-सम्मति से यह बिल पास भी होगा, ऐसा मैं मानता हूं ।

सभापति महोदय, इस चर्चा में कई माननीय सदस्यों ने भाग लिया, करीब 21 लोगों ने भाग लिया । श्री कार्ती पी. चिदम्बरम जी से शुरू किया और अभी लास्ट में श्री संतोष पान्डेय जी ने इसमें भाग लिया । आपने भी इस चर्चा में भाग लिया । मैं सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । विषय बहुत छोटा सा था, लेकिन इसमें चर्चा करीब-करीब तीन घंटे से ज्यादा की हो गई ।

चेयरमैन सर, मैं सबसे पहले आपके सब्जेक्ट का ही जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, आपने बहुत टैक्निकल सब्जेक्ट उठाया था । यह 1879 का एक्ट है, यह कोलोनियल एक्ट है और रिपील होना चाहिए । श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने यह तय किया है कि जो कोलोनियल लॉ है, जिसकी यूटिलिटी नहीं है, जिसका श्री भर्तृहरि महताब साहब जिक्र कर रहे थे, वे समाप्त होने चाहिए । देश में भी इसका स्वागत हुआ । (व्यवधान) अब तक ऐसे 1,486 लॉज़ समाप्त हो चुके हैं । (व्यवधान) अभी कुछ और लॉज़ भी पाइपलाइन में हैं, उनको फिर एक साथ लेकर आएंगे ।

आपका क्वेश्चन था कि क्या सेक्शन 36 आप 1961 में इनकॉरपोरेट कर रहे हो? क्या आप चाहते थे कि 1879 का लॉ एज़-इट-इज़ रहे? हम उसे रिपील कर रहे हैं, लेकिन 1936 का जो यह टाउट वाला सब्जेक्ट है, यह कमेटी को भी ठीक लगा, हमारे डिपार्टमेंट को भी ठीक लगा, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भी ठीक लगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी ठीक लगा, क्योंकि वकील की ड्रेस में बहुत से लोग ऐसे आते हैं, जो वकील नहीं हैं, उनकी डिग्रियाँ भी फर्जी हैं । वे आकर किसी को ठगते हैं तो उसका क्या प्रावधान हो? यह ऑलरेडी 1879 में प्रावधान था, इसको उठाकर हम 1961 में लाए हैं, छोटा सा अमेंडमेंट था, 45(ए) हमने इन्सर्ट किया । इसका उद्देश्य बिल्कुल पवित्र है । जो कालोनियल लॉ हैं, जिनकी यूटिलिटी नहीं है, उन्हें हम समाप्त करेंगे । 1961 तो हमने, इसी सदन ने पास किया । जो आप कह रहे थे कि टाउट सब्स्टिटूशन है, 1961 में उस समय की सरकारों ने यह सोचा नहीं कि पुराने जो कालोनियल लॉ हैं, उन्हें भी समाप्त करना है । मैं यूपीए के 10 साल का आपको विवरण दूँगा । हमने अभी माननीय नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद 1,486 कानून समाप्त कर दिए हैं । मनमोहन सिंह जी के समय 10 साल आप भी थे, एक भी ऐसा कालोनियल लॉ उन्होंने रद्द नहीं किया । इसका मतलब है कि उनकी सोच ही नहीं थी । हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि पंच प्रण, जिसका जगदम्बिका पाल साहब जिक्र कर रहे थे, विकसित भारत मानव केन्द्रित, हमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाना है । विरासत पर गर्व, यह दूसरा प्रण है । तीसरा प्रण है कि गुलामी के हर चिन्ह से मुक्ति और वही मुक्ति लेने का काम हम लोग कर रहे हैं । एकता और एकजुटता और नागरिकों द्वारा कर्तव्य पालन, ये कुछ विषय पंच प्राण के थे, जिनका मैंने जिक्र किया है । इसमें और बहुत से विषय आए हैं, उनका मैं थोड़ा-थोड़ा जिक्र करूंगा । अभी ए. राजा साहब उपस्थित नहीं हैं, लेकिन इतना नहीं बोलना चाहिए । ठीक है कि यहां प्रिविलेज है, लेकिन करप्शन तो समाज की प्रॉब्लम है । अगर कोई आदमी एग्जीक्यूटिव में है, कोई आदमी जुडीशियरी में है, कोई आदमी प्रेस में है, कोई आदमी लेजिस्लेटिव विंग में है, अगर वह करप्ट है तो वह समाज की प्राब्लम है, उसको दूर करना चाहिए । यह बात ठीक है, लेकिन आप किसी को इंडीकेट करो । उन्होंने कहा कि विजन और ऑब्जेक्ट हमें मिले ही नहीं हैं । यह बिल में ही लगे हुए हैं । उन्होंने या तो इसे पूरा देखा नहीं है । वे पूरे जुडीशियल सिस्टम को ही गड़बड़ बता गये । कल्याण बनर्जी साहब यहां बैठे हैं । इनसे टेलीफोन पर भी मेरी कुछ बात हुई थी । ट्रांसफर ऑफ जजेज़ पर इन्होंने कहा कि इसकी पॉलिसी होनी चाहिए । कांस्टीट्यूशन में ट्रांसफर ऑफ जजेज़, आप सबको पता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज़ 1993 के बाद कॉलेजियम के पास है । ट्रांसफर ऑफ जजेज़ का अभी कॉलेजियम से सिस्टम आता है । आपने कहा कि पिक एंड चूज । कॉलेजियम के सिस्टम पर हम कभी भी बहस कर सकते हैं, इसी हाउस को बहस करनी चाहिए । हम तो नेशनल जुडीशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर आए थे । आप भी उस पर बहुत अच्छा बोले थे, लेकिन जुडीशियल रिव्यू की पॉवर सुप्रीम कोर्ट को है । आपका सुझाव बहुत अच्छा है कि ट्रांसफर ऑफ जजेज़ में एक पॉलिसी जरूर होनी चाहिए । हम इसको स्वीकार करते हैं । आपकी बात को, जुडीशियरी या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके अगर कोई पॉलिसी बनती है तो हम आगे इसमें काम करेंगे । इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

भर्तृहरि महताब साहब ने बहुत अच्छा बिंदु रखा कि जिनकी यूटीलिटी नहीं है, वे एक्ट समाप्त हो रहे हैं । 1879 के इस एक्ट की भी यूटीलिटी नहीं थी । टाउट के संबंध में सबने कहा कि अगर कोई ठगी करेगा तो उसका क्या इलाज है, इसलिए हमने इसको इनकोरपोरेट किया है । बाकी अधिकतर बिंदु जो आए हैं, वेलफेयर ऑफ दी एडवोकेट का विषय आया, इंश्योरेंस, लायर्स के चैंबर्स, सिक्योरिटी, ये सारे विषय आये हैं । नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, चाहे कोई वर्ग हो, कोई प्रोफेशनल सैक्शन हो, सबका साथ, सबका विकास, यह हमारा मूल मंत्र है तो वकील कैसे पीछे छूट जाएंगे । वकील भी पीछे नहीं छूटेंगे । इंश्योरेंस का विषय मैं खुद डील कर रहा हूं । मैंने राज्य सभा में भी कहा है और अभी संविधान दिवस के अवसर पर मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फंक्शन में गया था, वहां भी मैं कहकर आया हूं कि इंश्योरेंस में अगर आपको कंट्रीब्यूशन देने में कोई दिक्कत है तो आप प्रपोजल लेकर आइए । सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लोग जल्दी प्रपोजल लेकर आएंगे । हम मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में या मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स में जहां भी जरूरत होगी, भारत सरकार पैसे देने में कोई कंजूसी नहीं करेगी, जो प्रपोजल विजिबल होगा ।

महोदय, हमारे वकील भी इतने ही प्रोफेशनल हैं जितने कि डॉक्टर्स हैं । उनके लिए सिक्योरिटी का कोई विषय आया, तो इनके लिए भी हम जरूर कुछ न कुछ करेंगे । एक विषय यह आया कि टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो रहा है । यह बात मुझे समझ नहीं आई क्योंकि दस-बारह साल पहले जब आप कोर्ट परिसर में जाते थे, तो आप किसी न किसी से पूछते थे कि मेरी पेशी कब है । आज वहां टच मशीन लगी हुई है । आप अपना नम्बर डॉयल करें, उसमें नाम लिखें तो पता चल जाएगा कि इस कोर्ट नम्बर में आपकी पेशी है । यह मोदी जी की सरकार है, क्या यह बात आपको समझ नहीं आई? मोदी जी की सरकार में ईज ऑफ लीविंग हमारी प्रायोरिटी है । मुझे सदन को बताते हुए परम हर्ष हो रहा है कि हमारी एक स्कीम ई-कोर्ट चल रही है । इसके लिए 7280 करोड़ रुपये नरेन्द्र मोदी जी ने सैंक्शन किए हैं । सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बनी हुई है और जहां-जहां भी विडियो कांफ्रेंसिंग की जरूरत है, जैसे किसी ने कहा कि बैंच नहीं हैं । मलूक नागर साहब चले गए हैं । उन्होंने कहा कि मेरठ में बैंच नहीं हैं । सुप्रीम कोर्ट और हम लोग मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं कि विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हम दावा पेश करने का, बेल ग्रांट करने की क्या सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं । यह बहुत अच्छा कदम है कि अगर किसी वजह से बैंच नहीं बनी, क्योंकि बैंच बनाने के लिए संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, उसके बाद चीफ मिनिस्टर की कंसेंट चाहिए । कई बार कंसेंट नहीं मिलती है लेकिन हम वीसी के माध्यम से हाई कोर्ट की सुविधा जैसी यदि सुविधा उपलब्ध करा दें तो उसमें दिक्कत क्या है? इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

मैंने राज्य सभा में कहा था कि वकील कई तरह के होते हैं । हम यह जो एक्ट लेकर आए हैं, मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं । महर्षि अरविंद बहुत बड़े संत हुए । इन्होंने डिवाइन लाइफ तथा कई अन्य पुस्तकें लिखीं । अलीपुर बम केस में वे आरोपी थे । किसी ने कहा कि इन्हें सजा होगी और फांसी होगी । एक अखबार में छपा कि शायद मजिस्ट्रेट इन्हें फांसी की सजा देने वाले हैं । श्री चितरंजन दास, जो इनके वकील नहीं थे लेकिन एक प्रसिद्ध वकील थे, जिसका जिक्र जगदम्बिका पाल जी ने भी किया । चितरंजन दास जी अखबार में यह खबर पढ़ कर कोर्ट में पेश हो गए । जज साहब ने पूछा कि क्या आप इनके वकील हैं? उन्होंने कहा कि मैं इनका वकील नहीं हूं लेकिन क्या मैं इनके लिए बहस नहीं कर सकता हूं । जज ने अरविंद घोष जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई वकील नहीं किया है लेकिन फिर भी चितरंजन दास जी ने कहा कि मैं बहस करूंगा । चितरंजन दास जी ने एक बात कही कि जज साहब आप मर जाओगे, मैं मर जाऊंगा लेकिन जो अरविंद घोष का थॉट है, वह हमेशा अमर रहेगा । उन्होंने दो घंटे से ज्यादा बहस की और कोई फीस नहीं ली । हमारे यहां ऐसे भी तो वकील हुए हैं । उस बहस के बाद महर्षि अरविंद को जज ने छोड़ दिया, इक्टिल हुआ । इसके बाद उन्होंने पांडेचेरी में जाकर कितना बड़ा काम किया । ऐसे भी तो वकील हुए हैं ।

सभापति जी, कुछ अच्छे सुझाव आए हैं और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं । हमने एक बड़ा काम संविधान दिवस के अवसर पर किया, जिसका जिक्र करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । संविधान दिवस पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी । बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगी और उस अवसर पर लगी जब बाबा साहब को वकील के रूप में सौ साल पूरे हुए । मैं सुप्रीम कोर्ट का इस अवसर पर धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि मुख्य लॉन के परिसर में यह मूर्ति लगी है और जो बाबा साहब ने कहा था कि कुछ ऐसे गरीब लोग हैं, जिनके मुकदमे फ्री भी लड़ने चाहिए । जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी प्रतिमा लग गई है, तो वह भी हमें दिशा दिखाएगी और सही दिशा में देश चल रहा है । यह जो छोटा-सा अमेंडमेंट है, जैसा मैंने कहा कि Advocates (Amendment) Bill, 2023, as passed by Rajya Sabha, इसे आप सर्वसम्मति से पास करें, ऐसी मैं आपसे विनती करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

18.00 hrs

*m26 HON. CHAIRPERSON : It is already 6 oclock. If the House agrees, we will extend the sitting till this Bill is passed.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Now, the Bill will be taken up for consideration and passing.

प्रश्न यह है:

कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

HON. CHAIRPERSON: Amendment Nos. 3, 6 and 8 to10 to clause 2, Prof. Sougata Ray ji not present.

प्रश्न यह है:

कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(व्यवधान)

*m27 SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Hon. Chairperson, Sir, I beg to move:

That the Bill be passed.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाक 5 दिसम्बर, 2023 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(व्यवधान)

18.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on

Tuesday, December 05, 2023/Agrahayana 14, 1945 (Saka).